सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 209, नई दिल्ली | बुधवार, 11 अक्टूबर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

आज का सुविचार

यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो इसे एक लक्ष्य से बांधें न कि लोगों या चीजों से !

दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी खबर, PUC नहीं है तो हो जाएं सावधान; कटेगा 10 हजार रुपये का चालान

संजय बाटला, सम्पादक

दिल्ली में पंजीकृत 23 लाख से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जिनके PUC Certificate अमान्य हो चुके हैं। विभाग ने ऐसे वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहले ऐसी ही गाड़ियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि ऐसे लोग अगर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराने के लिए जाएं तो उनके खिलाफएक्शन लिया जा सके।

नई दिल्ली। प्रदूषण का स्तर खराब होने के साथ ही परिवहन विभाग प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कदम उठाने के लिए सक्रिय हो गया है। गाड़ियों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विभाग ने दो दिन पहले प्रवर्तन यूनिट की 60 से ज्यादा टीमों को अलग-अलग जगहों पर तैनात कर दिया है।

ताकि जिन गाड़ियों के पास अधिकृत प्रदूषण नियंत्रण (PUC Certificate) प्रमाणपत्र नहीं हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके। दिल्ली में पंजीकृत 23 लाख से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं, जिनके पीयूसी प्रमाणपत्र अमान्य हो चुके हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ विभाग ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की टीमें दो पहिया और चार पहिया वाहनों की भी जांच करने जा रही हैं। विभाग ने इसके भी निर्देश दे दिए हैं। परिवहन विभाग ने उन सभी वाहन चालकों को एसएमएस के जरिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिनके पीयूसी की वैधता खत्म हो चुकी है।

हफ्ते भर के अंदर करवा लें अपने वाहन की पीयूसी जांच

ऐसे लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर उन्होंने हफ्ते भर के अंदर अपने वाहन की पीयूसी जांच करवा के पीयूसी प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं कराया, तो फिर उन्हें 10-10 हजार रुपये के जुर्माने के चालान भेजे जाएंगे। परिवहन विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इनमें से कितनी गाड़ियां ऐसी हैं, जो वास्तव में बिना पीयूसी के सड़कों पर चल रही हैं।

कैसे बनवाएं पीयूसी सर्टिफिकेट ? नियमों का उल्लंघन करने वालों का इतने हजार का कटेगा चालान

सबसे पहले ऐसी ही गाड़ियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि ऐसे लोग अगर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराने के लिए जाएं, तो उनके खिलाफ वहीं पर एक्शन लिया जा सके।

परिवहन विभाग के अनुसार जिन 23 लाख गाड़ियों के पीयूसी प्रमाणपत्र की उम्र पूरी हो चुकी है, उनमें से करीब 19 लाख दो पहिया हैं, जबकि साढ़े तीन लाख चार पहिया और बाकी अन्य व्यावसायिक वाहन हैं।

प्रतिबंध के बावजूद चल रहे पुराने वाहन

इसे देखते हुए प्रवर्तन टीमों को खासतौर से यह हिदायत दी गई है कि वे पुराने नंबरों वाले दो पहिया पर भी कड़ी नजर रखें और पेट्रोल पंपों व अन्य जगहों पर उनके पीयूसी प्रमाणपत्र चेक करें। इसके अलावा प्रतिबंध के बाद भी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चल रहे हैं, जो प्रदूषण का बड़ा कारण बन रहे हैं।

विशेषज्ञों की मानें तो दिल्ली में बसें बढ़ाने के साथ साथ उन्हें व्यवस्थित करने की भी जरूरत है जिससे कि लोगों को पता हो कि किस बस स्टैंड पर किस रूट की कितने बजे बस आ रही है। लोग जब मेट्रो से उतरें तो उन्हें उनके घर तक जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सके।

22 कॉरिडोर्स पर प्रवर्तन विंग की 44 टीमें की गई तैनात

ऐसे माहौल में लोग अपने निजी वाहन त्याग कर सार्वजनिक वाहनों की ओर रुख करेंगे। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बस लेन एनफोर्समेंट के लिए चिह्नित किए गए 22 कॉरिडोर्स पर प्रवर्तन विंग की 44 टीमें तैनात की गई हैं।

ये टीमें चार पहिया गाड़ियों के जरिए इन कारिडोर्स पर पेट्रोलिंग करके यह देखेंगी कि बसें व अन्य भारी वाहन अपनी लेंन में चलें और उनकी वजह से कहीं पर भी यातायात जाम पैदा ना हो। इसके अलावा 16 टीमें दिल्ली की सीमा पर तैनात की गई हैं, जो ट्रकों व अन्य व्यावसायिक वाहनों में होने वाली ओवरलोडिंग की जांच करेंगी।

छह महीने में भोपाल रेल मंडल ने कमाए एक हजार करोड़ ऐसे हुई इतनी आमदनी, वंदे भारत बैतूल में भी रुकेगी

परिवहन विशेष न्यूज

भोपाल। चालू वित्तीय वर्ष के पहले छह महीने में भोपाल रेल मंडल को 1044.32 करोड़ रुपये की कमाई हुई। जो पिछले साल की इसी अवधि में 926.88 करोड़ रुपये की तुलना में 12.67 प्रतिशत ज्यादा है। इसके साथ वंदे भारत ट्रेन अब बैतूल में भी रुकेगी।

पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल ने छह महीने में एक हजार करोड़ की कमाई की है। जो पिछले साल की आमदनी से 12 प्रतिशत से भी अधिक है। जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम छमाही (अप्रैल से सितंबर 2023 तक) में मंडल को कुल 1044.32 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व 926.88 करोड़ रुपये से 12.67 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 193.56 लाख बुक किए गए यात्रियों से 472.07 करोड़ रुपये, अन्य कोचिंग से 27.97 करोड़ रुपये, माल परिवहन से 513.46 करोड़ रुपये, विविध आय से 30.82 करोड़ रुपये शामिल है।

बता दें कि मंडल की इस उपलब्धि पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने कहा कि भोपाल मंडल रेल प्रशासन अपने सम्माननीय रेल उपभोक्ताओं को शिकायत रहित सेवा प्रदान करने के प्रति कृत संकल्प है। साथ ही रेल राजस्व बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील है।

इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत को मिला बैतूल में हाल्ट

वंदे भारत से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 20911/20912 इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को बैतूल स्टेशन पर हॉल्ट देने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार गाड़ी संख्या 20911 इंदौर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में छह दिन, रविवार को छोड़कर अब बैतूल स्टेशन पर भी रुकेगी। यह ट्रेन इंदौर स्टेशन से 06.10 बजे प्रस्थान कर, 06.50 बजे उज्जैन पहुंचकर, 06.55 बजे उज्जैन से प्रस्थान कर, 09.10 बजे भोपाल पहुंचकर, 09.15 बजे भोपाल से प्रस्थान कर, 10.35 बजे इटारसी पहुंचकर, 10.40 बजे इटारसी से प्रस्थान कर, 11.58 बजे बैतूल पहुंचकर, 12.00 बजे बैतूल से प्रस्थान कर, 14.30 बजे नागपुर स्टेशन पहुंचेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 20912 नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस (सप्ताह में छह दिन, रविवार को छोड़कर) नागपुर स्टेशन से 15.20 बजे प्रस्थान कर, 17.23 बजे बैतूल पहुंचकर, 17.25 बजे बैतूल से प्रस्थान कर, 18.50 बजे इटारसी पहुंचकर, 18.55 बजे इटारसी से प्रस्थान कर, 20.30 बजे भोपाल पहुंचकर, 20.35 बजे भोपाल से प्रस्थान कर, 22.40 बजे उज्जैन पहुंचकर, 22.45 बजे उज्जैन से प्रस्थान कर, 23.45 बजे इंदौर स्टेशन पहुंचेगी।

डीटीसी मार्शलों का 2 माह में तीसरा प्रदर्शन

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। मंगलवार को डीटीसी मार्शलों ने उपराज्यपाल निवास पर पिछले 5 महीनें से सैलरी नहीं मिलने पर दो महीनें में तीसरा जबरदस्त प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में प्रदर्शन- - कारियों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां पकडी हुई थी तख्तियों पर पांच महीने से वेतन नहीं, जवाब दो। भूखे, युवा मार्शलों से अन्याय क्यों। मार्शलों की जान पर राजनीति बंद करो, इंक्लाब जिंदाबाद, एलजी साहब बाहर आओ, सीएम साहब न्याय करो। जैसे नारे लगा रहे थे। इस बावत विवेक मिश्रा ने बताया कि बच्चों की खातिर काम के बदले भीखारियों की तरह हम सबके आगे झोली फैलाकर चिरौरी कर पिछले 5 महीने की सैलरी की भीख मांग रहे हैं।इसके लिए दो महीने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, डीटीसी हेड क्वार्टर और आज मंगलवार 10 अक्टूबर को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की चौखट में हजारों मार्शल अपने वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। तमाम मंत्री, सचिवालय के अधिकारी, कमिश्नर, हम लोगों को फुटबाल की तरह एक दूसरे के दरवाजे पर किक मार रहे हैं। लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी,सीएम, सुनने को तैयार नही है। एक महिला मार्शल ने कहा कि मेरे पति नहीं हैं। मैं अपने तीन बच्चों का लालन पालन इसी नौकरी से करती हूं। पिछले पांच माह की सैलरी ना मिलने से हम सबकी भूखों मरने की हालत हो गई है। अब तक तीन से चार मार्शल अपनी जान गंवा चुके हैं। लगता है गूगीं बहरी दिल्ली सरकार के सामने तमाम मार्शल सामूहिक आत्मदाह करेंगे तब ही इनकी नींद टूटेगी। मार्शल सितंबर की 18, और 29 को डीटीसी हेड क्वाटर, समेत आज 10 अक्टूबर को उपराज्यपाल से अपनी परेशानी से ब्यां करने आए हैं। अगर फिर भी सरकार सैलरी नहीं देती है, तो बीबी बच्चों समेत सामूहिक आत्मदाह ही एक रास्ता बचता है। पांच महीने का मकान का किराया, स्कूल फीस, किताब-कॉपी, राशन वाले की उधारी चढती जा रही है। इसका समाधान कौन करेगा? सब मौन है।

विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम नही मानते जिला मजिस्ट्रेट का आदेश

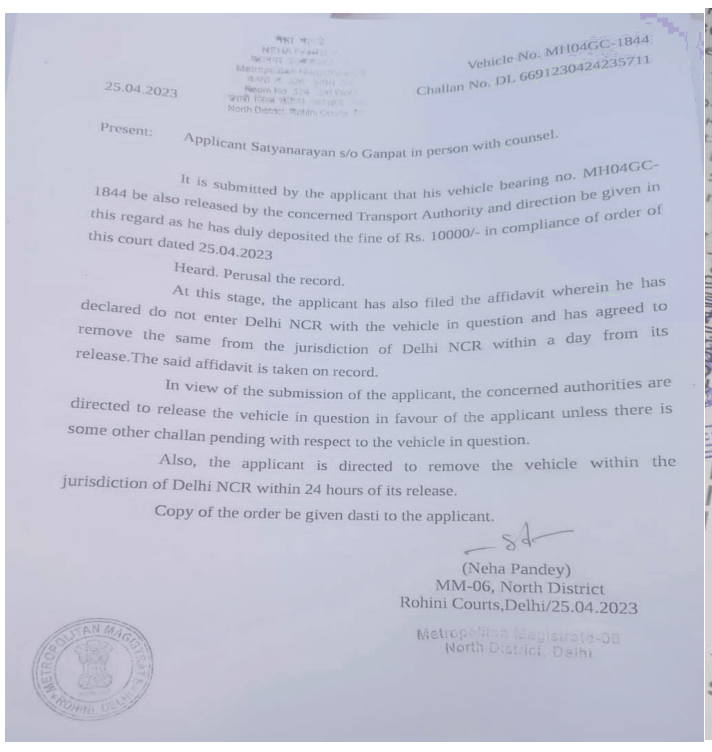

25.04.2023

Vehicle No. MH04GC-1844
Challan No. DL 6691230424235711

Present: Applicant Satyanarayan s/o Ganpat in person with counsel.

It is submitted by the applicant that his vehicle bearing no. MH04GC-1844 be also released by the concerned Transport Authority and direction be given in this regard as he has duly deposited the fine of Rs. 10000/- in compliance of order of this court dated 25.04.2023

Heard. Perusal the record.

At this stage, the applicant has also filed the affidavit wherein he has declared do not enter Delhi NCR with the vehicle in question and has agreed to remove the same from the jurisdiction of Delhi NCR within a day from its release. The said affidavit is taken on record.

In view of the submission of the applicant, the concerned authorities are directed to release the vehicle in question in favour of the applicant unless there is some other challan pending with respect to the vehicle in question.

Also, the applicant is directed to remove the vehicle within the jurisdiction of Delhi NCR within 24 hours of its release.

Copy of the order be given dasti to the applicant.

(Neha Pandey)
MM-06, North District
Rohini Courts,Delhi/25.04.2023

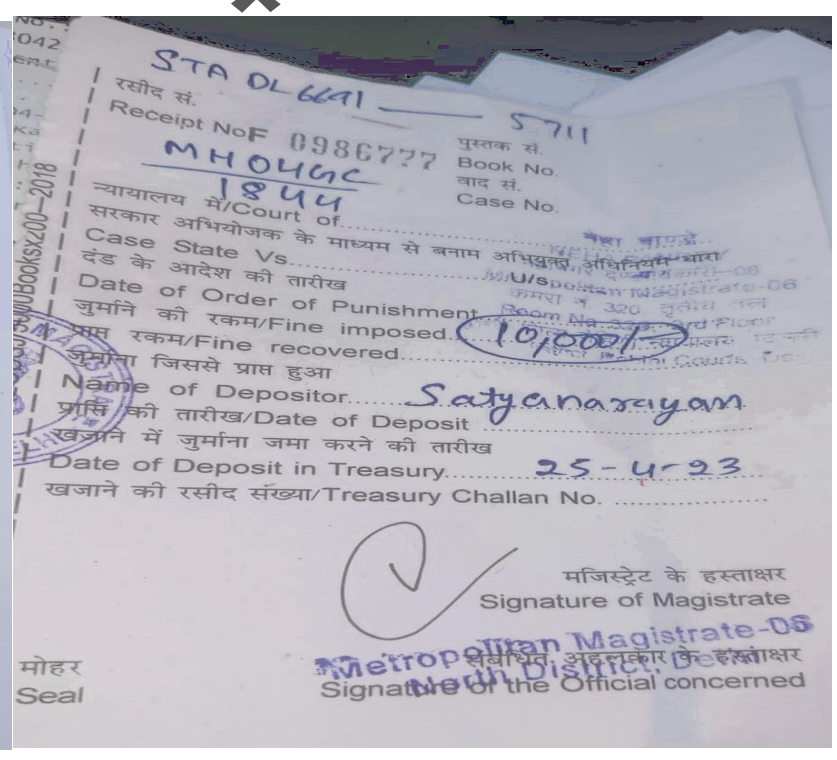

STA DL 6691 —— 5711
रसीद सं. Receipt No. F 0986777
पुस्तक सं. Book No.
वाद सं. Case No. MH04GC 1844
न्यायालय में/Court of ...
सरकार अभियोजक के माध्यम से बनाम अभियुक्त अधिनियम धारा
Case State Vs. ... U/s
दंड के आदेश की तारीख
Date of Order of Punishment
जुर्माने की रकम/Fine imposed 10,000/-
प्राप्त रकम/Fine recovered
जुर्माना जिससे प्राप्त हुआ
Name of Depositor Satyanarayan
प्राप्ति की तारीख/Date of Deposit
खजाने में जुर्माना जमा करने की तारीख
Date of Deposit in Treasury 25-4-23
खजाने की रसीद संख्या/Treasury Challan No.
मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर
Signature of Magistrate
मोहर
Seal
संबंधित अहलकार के हस्ताक्षर
Signature of the Official concerned
Metropolitan Magistrate-06
North District, Delhi

परिवहन विशेष न्यूज

नईदिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग में स्पैशल कमिश्नर के पद पर कार्यरत शहजाद आलम का कहना है की वह जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी चालान पर पारित किए आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं और ना ही जिला मजिस्ट्रेट परिवहन विभाग को आदेश पारित कर सकता है जब की मोटर वाहन एक्ट और रूल में सपष्ट लिखा हुआ है की प्रवर्तन शाखा द्वारा किए गए किसी भी वाहन के चालान पर फैसला करने ओर आदेश पारित करने का अधिकार सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट का है पर शहजाद आलम द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को मानने से मना करने के साथ ही वाहन मालिक के वाहन को अपने पद की ताकत का दुरुपयोग कर गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में रख नुकसान पहुंचाने का कृत्य कर रहे हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्य सचिव ओर परिवहन आयुक्त चुप है क्या ऐसे गैर कानूनी कार्य करने के लिए उनकी शह है शहजाद आलम को, बड़ा सवाल?

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

तेजी से बढ़ रहा प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत का आंकड़ा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

गाजियाबाद में प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल से 8 अक्टूबर तक 10 महिलाओं की मौत हो चुकी है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मौत रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत शहरी और देहात क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं का सर्वे किया जाएगा।

गाजियाबाद। प्रसव के दौरान अथवा बाद में अधिक रक्त स्राव होने और हीमोग्लोबिन कम होने से गाजियाबाद में महिलाओं की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल से 8 अक्टूबर तक 10 महिलाओं की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने मौत रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

इस अभियान के तहत शहरी और देहात क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं का सर्वे किया जाएगा। आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की सेहत का हाल-चाल पूछने के लिए उनके घर जाएंगी। नियमित टीकाकरण के साथ गर्भवती महिलाओं को बेहतर खान-पान के बारे में भी जागरूक किया जाएगा ।प्रत्येक माह की 1 ,9 , 16 और 24 को होने वाले विशेष आयोजन के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की निशुल्क जांच कराई जाएगी।

इस जांच में यह भी पता चल जाएगा की महिला में खून की कमी है अथवा नहीं ,और यदि खून की कमी होगी तो तुरंत महिला को खून चढ़ाया जाएगा। प्रसव के लिए महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

पिछले 6 महीने में 7000 से अधिक महिलाओं के प्रसव संस्थागत हुए हैं। इनमें जिला महिला अस्पताल में सबसे अधिक प्रसव हो रहे हैं ।कई बार सिजेरियन प्रसव के दौरान चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की वजह से भी महिला की मौत हो रही है। पिछले साल ऐसे 32 मामलों में जांच करने के बाद लापरवाही उजागर हुई है। सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंखधर ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को मजबूती से लागू करने हुए घर-घर जाकर गर्भवतियों का पता लगाया जाएगा।

सभी गांठें नहीं होती हैं ब्रेस्ट कैंसर, करती हैं इन बीमारियां की ओर इशारा

आजकल ज्यादातर महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आ रही हैं। इसके चलते इसको लेकर जागरूकता महिलाओं के बीच बढ़ी है। महिलाओं अकसर खुद घर पर ही अपने ब्रेस्ट में गांठ के लिए चेक करती रहती हैं। ब्रेस्ट में किसी तरीका का परिवर्तन बहुत चिंता का कारण बन सकता है। ये तो समझ में आता है। लेकिन हर बार ब्रेस्ट में परिवर्तन की वजह ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती हैं।

ब्रेस्ट में कोई भी लक्षण, जैसे कि ब्रेस्ट में गांठ, निपल से स्राव या ब्रेस्ट में दर्द, आदि की जांच करके इसकी सही वजह एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। आपको बता दें ब्रेस्ट के जुड़ी और भी लक्षण होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की ओर नहीं बल्कि किसी और बीमारी की ओर इशारा करते हैं। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में....

फाइब्रोएडीनोमा

फाइब्रोएडीनोमा ब्रेस्ट का सबसे आम किस्म का ट्यूमर है। ज्यादातर ये 15 से 35 साल की उम्र के लोगों में होते हैं। ब्रेस्ट examination के दौरान में ये अक्सर एक सख्त, गोल, चिकनी और रबड़ जैसी स्तन गांठ के रूप में दिखाई देते हैं। कई फ़ाइब्रोएडीनोमा का समय-समय पर अल्ट्रासाउंड करके इलाज किया जा सकता है। ये भविष्य में स्तन कैंसर के खतरे को नहीं बढ़ाते हैं।

ब्रेस्ट सिस्ट

कभी-कभी, ब्रेस्ट में सिस्ट विकसित हो सकते हैं। सिस्ट तरल पदार्थ से भरे सेल्स होते हैं। ये breast tissue में गांठों या मैमोग्राम पर पाई जा सकती हैं। वे हमेशा लक्षण पैदा नहीं करते हैं, लेकिन जैसे- जैसे सिस्ट बढ़ते हैं ब्रेस्ट में दर्द और sensitivity पैदा होती हैं। ये 35 से 60 साल की उम्र के बीच आम हैं, और पीरियड्स के साथ उतार-चढ़ाव हो सकता है। वहीं ब्रेस्ट में सिस्ट ब्रेस्ट कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता है।

मास्टिटिस

ये ब्रेस्ट tissue में एक तरह की सूजन है जो ब्रेस्ट में दूध नलिकाओं के ब्लॉक होने से या बैक्टीरिया के कारण होती है। यह आमतौर पर ब्रेस्टफीड करवाने वाली महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन यह उन महिलाओं में भी हो सकता है जो ब्रेस्टफीड नहीं करवाती हैं। सूजन से ब्रेस्ट में दर्द, सूजन, गर्मी और लालिमा होती है। मास्टिटिस का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं और दर्द निवारक दवाओं से किया जा सकता है।

पैपिलोमा

पेपिलोमा milk duct में एक वृद्धि है और यह निप्पल डिस्चार्ज के रूप में प्रकट हो सकता है। यह निप्पल के पीछे या बगल में एक छोटी गांठ के रूप में भी मौजूद हो सकता है। बायोप्सी यह समझने में मदद कर सकती है कि क्या पेपिलोमा का इलाज करने की जरूरत है या नहीं , क्योंकि कभी-कभी उनमें असामान्य कोशिकाएं हो सकती हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती हैं। वहीं इसका इलाज duct के बढ़े हुए आकार पर भी निर्भर करता है, यदि कई गांठें हैं या यदि वे लक्षण पैदा कर रहे हैं। पेपिलोमा को हटाने के लिए सर्जरी भी की जाती है।

असामान्य हाइपरप्लासिया (Atypical hyperplasia)

इसमें ब्रेस्ट की दूध नलिकाओं (milk ducts) में असामान्य कोशिकाओं यानी सेल्स बनते है। बता दें एटिपिकल हाइपरप्लासिया कोई कैंसर नहीं है, लेकिन इससे जरूर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से, कभी-कभी उस क्षेत्र को सर्जरी से हटा दिया जाता है। अक्सर, एक्सपर्ट्स कैंसर के खतरे को कम करने के लिए उस क्षेत्र को सर्जरी से हटा दिया जाता है। वहीं इसके इलाज के लिए खूब सारी screenings और दवाएं लेने की सलाह दी जाती है।

कामकाजी महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली क्लॉडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज

हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 'रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज' के महासचिव हैंस एलेग्रेन ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। गोल्डिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के वेतन में अंतर के कारणों को समझने के लिए काफी शोध किया है।

अर्थशास्त्र विज्ञान क्षेत्र में पुरस्कार विजेता का चयन करने वाली समिति के प्रमुख जैकब स्वैनसन ने कहा- ''श्रम बाजार में महिलाओं की भूमिका को समझना समाज के लिए महत्वपूर्ण है। क्लॉडिया गोल्डिन के अभूतपूर्व शोध के लिए धन्यवाद, अब हम अंतर्निहित कारकों के बारे में और अधिक जानते हैं तथा भविष्य में किन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता हो सकती है।"

गोल्डिन ने अमेरिका के 200 साल के इकनॉमिक इतिहास में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन किया। पुरस्कार समिति के सदस्य रैंडी एच. ने कहा कि गोल्डिन समाधान पेश नहीं करती हैं, लेकिन उनका शोध नीति निर्माताओं को समस्या से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा- ''गोल्डिन (श्रम बाजार में) लैंगिक भेदभाव के मूल स्त्रोत पर ध्यान आकर्षित करती हैं और यह कि समय के साथ तथा विकास के क्रम में इसमें किस तरह बदलाव आया। इसलिए, कोई एक नीति काफी नहीं है।"

एलेग्रेन ने बताया कि पुरस्कार की घोषणा के बाद 77 वर्षीय गोल्डिन ''आश्चर्यचकित और बेहद खुश" हुईं। नोबेल पुरस्कार के तहत विजेता को 10 लाख डॉलर का पुरस्कार दिया जाता है। दिसंबर में ओस्लो और स्टॉकहोम में होने वाले पुरस्कार समारोहों में विजेताओं को 18 कैरट का स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा भी दिया जाता है।

बता दें कि क्लाउडिया गोल्डिन फिलहाल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर के तौर पर कार्य कर रही हैं। वह एनबीईआर के जेंडर इन द इकोनॉमी ग्रुप की को-डायरेक्टर भी हैं। क्लाउडिया गोल्डिन 1989-2017 के दौरान एनबीईआर के अमेरिकन इकोनॉमिक प्रोग्राम की डेवलपमेंट डायरेक्टर थीं। उन्होंने कहा कि डिटेक्टिव होने के पीछे सोच ये रहती है कि आप खुद से सवाल पूछते रहें और उनके सवालों के जवाब मिलने तक कार्यरत रहें. आज भी उनके अंदर ये सोच जिंदा है।

वजन कम करने से लेकर पाचन स्वस्थ रखेगी मिक्स दाल, जानिए इसके बेशुमार फायदे

दाल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है इसलिए घरों में एक बार इसे जरुर खाते हैं। दाल खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। पहले समय में दालों को मिक्स करके बनाया जाता था इस तरह की दाल स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों को बढ़ाती है। मिक्स दाल को कई दालों के साथ मिलाकर बनाया जाता है जैसे अरहर, मूंग, चना, मसूर और उड़द की दाल इसमें शामिल की जाती है। इन सारी दालों में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। इस दाल का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है और शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि मिक्स दाल खाने से शरीर को और क्या-क्या फायदे होंगे....

वजन होगा कम

मिक्स दाल का सेवन करने से वजन कम करने में भी सहायता मिलती है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरकर रखता है जिससे भूख कम लगती है। इससे खाने की इच्छा शक्ति भी कम होती है जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मिक्स दाल में कैलोरी की मात्रा भी काफी कम मौजूद होती है। ऐसे में यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

बीमारियों से होगा बचाव

इसके अलावा मिक्स दाल खाने से डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां भी नियंत्रण में रहती हैं। इन दालों में फैट कम मात्रा में पाया जाता है जिससे दिल संबंधी बीमारियोंका जोखिम कम होता है। इसमें मौजूद फाइबर हार्ट को हेल्दी रखने में भी मदद करता है।

हड्डियां बनेगी मजबूत

मिक्स दाल में कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है यह हड्डियों को मजबूत बनाने और मांसपेशियों में होने वाले दर्द को भी कम करने में भी मदद करती हैं। मिक्स दाल खाने से कमजोरी दूर होती है और शरीर को ताकत मिलती है।

पाचन रहेगा स्वस्थ

यह पाचन संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए भी बेहद लाभकारी मानी जाती हैं। इसका सेवन करने से पेट साफ होता है और कब्ज की समस्या में भी आराम मिलता है। इसके अलावा मिक्स दाल खाने से अपच, गैस, बदहजमी और एसिडिटी से भी राहत मिलती है।

इम्यूनिटी बनेगी मजबूत

मिक्स दाल का सेवन करने से मौसमी बीमारियों से भी बचाव होता है क्योंकि इसमें विटामिन-सी काफी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर बीमारियों से बचाने में मदद करता है। मिक्स दाल खाने से वायरल बीमारियों का खतरा कम होता है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है।

सांसद संजय सिंह की रिमांड तीन दिन के लिए बढ़ी, ईडी बोली- सहयोग नहीं कर रहे आप नेता

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज मंगलवार को ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। पेशी पर जाने के दौरान आप नेता संजय ने कहा कि ईमानदार लोग हमारे साथ और बेईमान पीएम मोदी के साथ हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज मंगलवार को ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संजय सिंह की हिरासत को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया है।

जांच में सहयोग नहीं कर रहे आप नेता

ईडी ने कोर्ट से आप नेता संजय सिंह द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला देते हुए हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। वहीं, ईडी ने बताया कि संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश मिश्रा भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

ईमानदार लोग हमारे साथ हैं- संजय सिंह

अदालत में पेशी पर जाने के दौरान आप नेता संजय ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईमानदार लोग हमारे साथ और बेईमान पीएम मोदी के साथ हैं।

पेशी के दौरान न करें मीडिया से बात- कोर्ट

कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि इससे सुरक्षा संबंधी समस्या पैदा होती है। इसके साथ ही जज ने मीडियाकर्मियों को भी यह निर्देश दिया कि जब उन्हें (संजय) पेशी के लिए लाया जा रहा हो तो वे उनसे सवाल न पूछें।

पुलिस ने हिरासत में लिए आप कार्यकर्ता

वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं द्वारा यह विरोध आप विधायक अमानतुल्ला खान और संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ किया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों उग्र होते देख पुलिस ने कई को हिरासत में लिया है। ये लोग आप कार्यालय से डीडीयू मार्ग पर भाजपा मुख्यालय तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे।

बता दें कि आबकारी नीति मामले में ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पूछताछ के लिए आप नेता को कोर्ट में पेश कर पांच दिनों की रिमांड पर लिया था।

झूठा है शराब घोटाला: आप

केजरीवाल सहित आप नेताओं ने आरोपों का जोरदार खंडन किया है और दावा किया है कि जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए मामले झूठे हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह वर्तमान में समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं।

राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ AAP नेता राघव चड्ढा ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, इस मामले में हुए थे सस्पेंड

आप नेता राघव चड्ढा 11 अगस्त को हुए थे निलंबित
चार सांसदों ने की थी राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, जिसे लेकर राघव ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। राघव चड्ढा को 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित किया गया था। बता दें कि राघव चड्ढा के खिलाफ चार सांसदों ने विशेषाधिकार के उल्लंघन को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से निलंबित किया गया था।

'भ्रष्टाचारी AAP नेताओं को मिलता है झूठ बोलने का प्रशिक्षण...', भाजपा ने ऑडियो क्लिप जारी कर बोला हमला

भाजपा ने एक ऑडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोपित आम आदमी पार्टी के नेताओं को जांच एजेंसियों के सामने झूठ बोलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपराधियों व भ्रष्टाचारियों का संगठित गिरोह है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई से आप नेताओं के चेहरे पर हताशा झलक रही है।

नई दिल्ली। भाजपा ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर दावा किया कि भ्रष्टाचार के आरोपित आम आदमी पार्टी के नेताओं को जांच एजेंसियों के सामने झूठ बोलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है जिससे कि सच्चाई सामने आ सके।

सीबीआई से कराई जाए मामले की जांच- भाजपा

प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपराधियों व भ्रष्टाचारियों का संगठित गिरोह है। जांच एजेंसी की कार्रवाई से आप नेताओं के चेहरे पर निराशा व हताशा झलक रही है। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी किया, जिसमें एक व्यक्ति अन्य लोगों से बोल रहा है कि एक प्रश्न को कई तरह से पूछे जाते हैं। हमें सिर्फ उसी का सही उतर देना है जिसे हमें उन्हें बताना है। जिस बात का सही उत्तर नहीं देना है उसे किसी भी कीमत पर नहीं देना है। उसके बारे में सिर्फ झूठ बोलना है।

भाजपा में दिया जाता है जन सेवा का प्रशिक्षण- मनोज तिवारी

इस ऑडियो क्लिप की सीबीआई जांच जरूरी है जिससे पता चले कि आप का कौन नेता इस तरह का प्रशिक्षण दे रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा में जन सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं, आप में जांच एजेंसियों के सामने झूठ बोलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों को पार्टी से निकाल दिया जाता है। आप की सच्चाई सभी जान गए हैं। केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि वह किसी पार्टी से हाथ मिलाना तो दूर ऐसा सोचेंगे भी नहीं। उनका यह झूठ सबके सामने है। उन्होंने पहले कांग्रेस के साथ 49 दिनों की सरकार बनाई। अब आइएनडीआइए गठबंधन के हिस्सा हैं। लालू यादव सहित उसमें वह सभी नेता शामिल हैं जिन्हें केजरीवाल भ्रष्टाचारी बताते रहे हैं।

कोतवाली में ब्लॉक स्तरीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। जिलाधिकारी कार्यालय मध्य दिल्ली एवम नेहरू युवा केंद्र मध्य दिल्ली द्वारा कोतवाली में ब्लॉक स्तरीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया ,आजादी के 75वे अमृत महोत्सव के उपलक्ष में जनभागीदारी से जनआंदोलन के तहत इस कार्यक्रम में कोतवाली ब्लॉक के सभी वाड्र्स से आए कलश की मिटी एवम चावल को एक कलश में एकत्र किया गया। इस कार्यकम में मुख्यातिथि एडीएम, श्री अतुल पांडे जी, एसडीएम कोतवाली श्री अरविंद राणा जी थे। एसडीएम कोतवाली श्री अरविंद राणा जी द्वारा कलश यात्रा का नेतृत्व किया गया। एडीएम, श्री अतुल पांडे जी द्वारा सभी प्रतिभागियों को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई तथा युवाओं से आह्वान किया की इस देश की उन्नति में युवाओं का सबसे अहम योगदान है और देश के वीरों द्वारा दिए गए बलिदान को हमें कभी भी भुलाना नही चाहिए । इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र मध्य दिल्ली तथा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भागीदारी रही। इस मौके पर श्री उदयवीर , जिला युवा अधिकारी, श्री हरीश माथुर, डीपीओ तथा कॉमन सर्विस सेंटर के सदस्य मौजूद थे।

खत्म हुई न्यूजक्लिक के प्रबीर पुरकायस्थ की पुलिस रिमांड, अदालत ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों को दिल्ली पुलिस ने उनकी पुलिस रिमांड खत्म होने पर अदालत के समक्ष पेश किया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया है।

इस थाने में महिला फरियादियों के लिए ACP ने खींची लक्ष्मण रेखा, लाइन खींचने की वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में आने वाली महिला फरियादियों के लिए ACP ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। इस रेखा को पार करने के लिए महिलाओं को महिला पुलिसकर्मी (Women Police) के साथ की जरूरत होती है। उनके न होने पर इस रेखा को पार करके महिला फरियादियों का ACP व थानाध्यक्ष से मिल पाना संभव नहीं हो पाता।

पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के कल्याणपुरी थाने में आने वाली महिला फरियादियों के लिए ACP ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। इस रेखा को पार करने के लिए महिलाओं को महिला पुलिसकर्मी (Women Police) के साथ की जरूरत होती है। उनके न होने पर इस रेखा को पार करके महिला फरियादियों का ACP व थानाध्यक्ष से मिल पाना संभव नहीं हो पाता।

बोर्ड पर क्या लिखा है ?

कल्याणपुरी थाने में ACP कल्याणपुरी आशीष कुमार का कार्यालय भी है। कल्याणपुरी थाने के अंदर महिला फरियादियों के पहुंचने की बॉर्डर लाइन तय कर रखी है। कल्याणपुरी थाने के गेट से छह से सात कदम की दूरी पर पूछताछ केंद्र के पास एसीपी के आदेश का एक बोर्ड लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ₹कोई भी महिला एसीपी या कल्याणपुरी थानाध्यक्ष दिनेश कुमार से मिलने आती है तो वह बिना महिला पुलिसकर्मी के इस जगह से आगे नहीं जाएगी"। इस तरह का फरमान यमुनापार के बाकी थानों व एसीपी कार्यालयों में देखने को नहीं मिला। कल्याणपुरी थाने का हाल तब ऐसा है जब रेंज की संयुक्त आयुक्त व जिला पुलिस उपायुक्त महिलाएं हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर दावे करते हैं कि वह पुलिसकर्मियों को सीखाते हैं कि थाने में आने वाले लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। फरियादियों को थाने में एक बेहतर माहौल देना चाहिए। सवाल यह अगर थाने में महिला पुलिसकर्मी नहीं होगी तो क्या थानाध्यक्ष व एसीपी किसी महिला फरियादी से मिलेंगे ही नहीं। यही महिलाओं का सम्मान है कि उनके लिए थाने के अंदर एक रेखा खींच दी गई। इस तरह के आदेश से क्या महिलाएं अपने साथ होने वाले अपराध को लेकर पुलिस अधिकारियों को खुलकर कुछ बोल पाएंगी। यह उनके लिए थाने का बेहतर माहौल है। आरोप है कि पुरुष इंस्पेक्टर तक भी बिना एसीपी की अनुमति के उनके कार्यालय के अंदर नहीं जा सकता। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने एसीपी के आदेश के पीछे की वजह बताई कि कई बार महिलाएं पुलिस के अधिकारियों को झूठे केस में फंसाने के लिए गलत आरोप लगा देती हैं। इससे अधिकारी की छवि खराब हो जाती है। इसलिए कई अधिकारी महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ही अपने कार्यालय में महिला फरियादियो से मिलते हैं। डीपीसी का दावा पुराना बोर्ड, अधिकारियों ने संज्ञान लेकर हटवाया था जिला पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अमृता गुगुलोथ का कहना है कि यह पुराना बोर्ड है। पुलिस अधिकारियों के मामला संज्ञान में आने के बाद बोर्ड को हटा दिया गया था। जब उन्हें रिपोर्टर ने बताया कि सोमवार दोपहर तक भी बोर्ड थाने में लगा हुआ था। अगर अधिकारियों ने बोर्ड को हटवा दिया था तो फिर कैसे थाने में बोर्ड लग गया। इसपर उन्होंने कहा कि वह इस मामले को दिखवाएंगी।

स्वतंत्र सिंह भुल्लर भारतीय मजदूर संघ दक्षिण दिल्ली के मीडिया संयोजक बनाये गए

नई दिल्ली। पत्रकार स्वतंत्र सिंह भुल्लर पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार अपनी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से कम कर रहे हैं। उनकी इस लग्न और मेहनत को देखते हुए कई संगठनो ने उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी है जिसका वह बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश ने श्री भुल्लर को दक्षिणी दिल्ली जिला का मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि श्री भुल्लर अपनी जिम्मेदारियां को हमेशा निभाते रहे हैं और वह मीडिया संयोजक के अपने कार्य को भी उतनी ही शिद्दत के साथ निभाते रहेंगे। वही स्वतंत्र सिंह भुल्लर ने भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश का आभार जताया है जिसने उन्हें जिला का मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की समस्या एवं संगठन के प्रचार प्रसार का काम वह लगातार करते रहेंगे। संघ ने उनके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका निर्वाह वह पूरे मनोयोग से करेंगे। स्वतंत्र सिंह भुल्लर को दक्षिण दिल्ली का मीडिया संयोजक बनाए जाने पर लोगों में काफी खुशी है की एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को दक्षिणी दिल्ली जिला के मीडिया का प्रभार सोपा गया है।

दिल्ली LG ने ऑथर अरुंधति रॉय और पूर्व कश्मीरी प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी, जानिए क्या है मामला

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) ने लेखक अरुंधति रॉय और पूर्व कश्मीरी प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह मामला वर्ष 2010 का है। राज निवास के अधिकारियों के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दोनों पर देश की एकता के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) ने लेखक अरुंधति रॉय और पूर्व कश्मीरी प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह मामला वर्ष 2010 का है। राज निवास के अधिकारियों के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीआरपीसी की धारा 196 के तहत अरुंधतिरॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। दोनों पर देश की एकता के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

राजद्रोह का केस चलाने के लिए राज्य की मंजूरी जरूरी

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी, CrPC) की धारा 196(1) के तहत कुछ अपराधों जैसे नफरत फैलाने वाले भाषण, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, घृणा अपराध, राजद्रोह, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने, दूसरों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना आदि के लिए मुकदमा चलाने को राज्य या केंद्र की मंजूरी जरूरी होती है।

जानकारी के अनुसार, इन दोनों के खिलाफ नई दिल्ली के मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट ने 27 नवंबर, 2010 को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। उस दौरान 29 नवंबर, 2010 को आईपीसी की धारा 153ए, 153बी और 505 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

देशद्रोह की धारा जोड़ने की मंजूरी नहीं

सक्सेना ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए माना कि दिल्ली में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान भड़काऊ भाषण देने पर अरुंधति रॉय और प्रोफेसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 153बी और 505 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध का मामला बनता है।

हालांकि राजद्रोह का मामला बनने के बावजूद आईपीसी (देशद्रोह) की धारा 124ए के तहत मंजूरी नहीं दी गई है, क्योंकि 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में निर्देश दिया है कि आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत दर्ज सभी लंबित मामलों, अपीलों और कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। बाद में देश के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने इस मामले को 12 सितंबर 2023 को संविधानपीठ को भेज दिया था।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर कहा था कि आईपीसी की धारा 124ए के तहत अपराध के लिए अभियोजन की मंजूरी देने के अनुरोध पर फिलहाल फैसला नहीं लिया जा सकता है। दो अन्य आरोपी- कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और दिल्लीविश्वविद्यालय के लेक्चरर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, जिन्हें तकनीकी आधार पर संसद हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, की मामले की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई है।

21 अक्टूबर 2010 को एक सभागार में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए समिति (सीआरपीपी) द्वारा आयोजित सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से विभिन्न व्यक्तियों/वक्ताओं द्वारा उत्तेजक भाषण देने के खिलाफ कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने 28 अक्टूबर 2010 को तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कान्फ्रेंस के दौरान कुछ वक्ताओं के बयानों का भी उल्लेख किया था।

इसके अलावा अरुंधति रॉय, एस.ए.आर गिलानी और एस.ए.एस गिलानी द्वारा दिए गए भाषणों की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई एक सीडी और डीवीडी को सीएफएसएल के कंप्यूटर डिवीजन में फोरेंसिक जांच के लिए एक दिसंबर 2017 को भेजा गया था, जिसमें पाया गया कि सीडी/डीवीडी तार्किक रूप से कार्यात्मक और शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं थी।

इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा राय और हुसैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए,153बी, 504, 505 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 13 के तहत सीआरपीसी कीधारा 196 के तहत अभियोजन की मंजूरी मांगी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में रॉय, हुसैन, तहरीक-ए-हुरियत के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी और एसएआर गिलानी के अलावा भीमा-कोरेगांव मामले के आरोपी माओवादी समर्थक वरवर राव भी वहां शामिल थे।

यहां बता दें कि मामले के दो अन्य आरोपियों कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और डीयू के लेक्चरर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी की मामले की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई है। उन्हें तकनीकी आधार पर संसद हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था।

'भारत में हिंदुओं का क्या होगा...', यति नरसिंहानंद ने इजरायल हमले के बाद पीएम मोदी को खून से लिखा खत

परिवहन विशेष न्यूज

शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि महाराज ने जिहाद से बचाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्त से पत्र लिखा है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने रक्त से पत्र में लिखा कि इजरायल एक स्वाभिमानी राष्ट्र है और वहां के स्वाभिमानी और दिलेर नेता अपने लोगों और अपनी मिट्टी के लिए मर मिटेंगे लेकिन भारत में हिंदुओं का क्या होगा।

गाजियाबाद। शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि महाराज ने जिहाद से बचाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्त से पत्र लिखा। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने रक्त से पत्र में लिखा कि इजरायल एक स्वाभिमानी राष्ट्र है और वहां के स्वाभिमानी और दिलेर नेता अपने लोगों और अपनी मिट्टी के लिए मर मिटेंगे।

उन्हें विजय या वीरगति में से एक तो अवश्य ही मिल जाएगी, लेकिन भारत में हिंदुओं का क्या होगा। जिहादी यहूदियों से हजार गुना ज्यादा नफरत मूर्तिपूजक हिंदुओं से करते हैं। यह पत्र डाक द्वारा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा।

यति नरसिंहानंद सीएम योगी को विरोधस्वरूप वापस करेंगे अपनी सुरक्षा

महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने वीडियो जारी करके कहा कि उनके शिष्य अनिल यादव का गनर वापस लेने के विरोध में वह बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी सुरक्षा भी वापस कर देंगे।

अंतरराष्ट्रीय जिहादियों से जितना खतरा उन्हें है, उससे ज्यादा खतरा उनके शिष्य अनिल यादव को है। कल पिंकी चौधरी के समर्थन में जिला मुख्यालय पर होने वाली हिंदुओं की 36 बिरादरियों की पंचायत को संबोधित करके वह लखनऊ जाएंगे।

चिंटेल्स पैराडिसो का टावर-H भी असुरक्षित घोषित, 15 दिन में खाली करने का आदेश

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए टावर एच में रहने वाले लोगों को अगले 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश जारी किया है। आइआइटी दिल्ली द्वारा जारी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में टावर जी को इंसानों के रहने के लिए असुरक्षित बताया गया है।

गुरुग्राम। चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी (Chintels Paradiso Society) का टावर-एच भी असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने टावर एच खाली करने का आदेश जारी किया।

जिलाधीश ने जारी किया खाली करने का आदेश

आइआइटी दिल्ली द्वारा जारी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में टावर जी को इंसानों के रहने के लिए असुरक्षित बताया गया है। चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटीः तीन साल में फ्लैट बनाकर देगा बिल्डर, जिसे मुआवजा चाहिए उसे मिलेगा इसके आधार पर जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए टावर एच में रहने वाले लोगों को अगले 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश जारी किया है। इस कार्य के लिए डीटीपी(ई) को नोडल अधिकारी एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आइपीसी की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हिट एंड रन के अनसुलझे मामलों को ट्रेस करेगी स्पेशल सेल, खुलेंगे अज्ञात पर दर्ज होने वाले मामले

अपराध मामलों के अधिवक्ता पंकज यादव ने बताया कि हिट एंड रन के मामलों में छह महीने से लेकर दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके तहत लगने वाली धाराएं भी जमानती होती हैं। पुलिस अपने स्तर पर ही आरोपित वाहन चालकों को जमानत देकर छोड़ सकती है। कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर आरोपित को सजा सकती है।

गुरुग्राम। इस साल सड़क हादसों में करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। अधिकतर मामले ऐसे भी होते हैं, जिनमें वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो जाते हैं और उनका पता नहीं चल पाता। इससे सड़क हादसे के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता। हिट एंड रन के ऐसे ही अनसुलझे मामलों को ट्रेस करने के लिए क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल सेल इस पर काम करेगी और पीड़ितों को न्याय दिलाएगी।

शहर की पुलिस व्यवस्था में किए गए कई बदलाव

डेढ़ महीने पहले गुरुग्राम पुलिस आयुक्त का पद संभालने वाले विकास अरोड़ा ने शहर की पुलिस व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं। इसी के तहत उन्होंने क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल सेल बनाई है। यह टीम ऐसे आरोपित वाहन चालकों की पहचान करेगी जो सड़क दुर्घटनाओं के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। सड़क हादसों के बाद अगर थाना पुलिस मामले की जांच में अक्षम होती है तो ऐसे केस स्पेशल सेल के हवाले कर दिए जाएंगे। टीम के सदस्य पहले सड़क हादसे के अनसुलझे मामलों को चिन्हित करेंगे और उन पर काम करेंगे। इसके बाद टीम सड़क हादसे वाली जगह पर जाएगी और वहां मौजूद आसपास के सीसीटीवी कैमरे और लोगों से पूछताछ कर वाहन चालकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी। इसके बाद वाहन चालकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल सेल की इस कार्रवाई से आगे आने वाले समय में हिट एंड रन के मामलों में भी कमी आने की संभावना है। खोजकर चालकों पर कार्रवाई होने से वाहन चालकों में भी डर बना रहेगा। इससे पहले भी इस तरह का एक सेल बनाया गया था, लेकिन टीम के सदस्यों का ट्रांसफर होने पर सेल की कार्य क्षमता प्रभावित हो गई थी और सेल भंग हो गया था।

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी गुरुग्राम पुलिस, इस मामले में होगी पूछताछ

प्रोडक्शन वारंट के दौरान लारेंस से खोड़ में दोहरे हत्याकांड के मामले में पूछताछ की जाएगी। एसटीएफ भी उससे पूछताछ कर सकती है। बता दें कि गत वर्ष 25 फरवरी को गांव खोड़ में पूर्व जिला पार्षद परमजीत ठाकरान और सुजीत ठाकरान को बाइक सवार बदमाशों ने उनके घर के नजदीक ही गोलियां मार दी थीं। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

गुरुग्राम। कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई को जल्द ही गुरुग्राम पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी। इसके लिए क्राइम ब्रांच ने तैयारी तेज कर दी है। गुरुग्राम पुलिस ने कोर्ट में 13 अक्टूबर को प्रोडक्शन वारंट के लिए याचिका दायर की है। सूत्रों के अनुसार लारेंस बिश्नोई फिलहाल पंजाब के किसी जेल में बंद है। प्रोडक्शन वारंट के दौरान लारेंस से खोड़ में दोहरे हत्याकांड के मामले में पूछताछ की जाएगी। एसटीएफ भी उससे पूछताछ कर सकती है। बता दें कि गत वर्ष 25 फरवरी को गांव खोड़ में पूर्व जिला पार्षद परमजीत ठाकरान और सुजीत ठाकरान को बाइक सवार बदमाशों ने उनके घर के नजदीक ही गोलियां मार दी थीं।

दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर है। मामले में गैंग के 20 से अधिक शूटर और अन्य गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पूछताछ के मुताबिक गैंग ने इलाके में वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक साथ तीनों भाइयों परमजीत ठाकरान, सुजीत ठाकरान और अजीत ठाकरान की हत्या करने की साजिश रची थी। वारदात के समय तीनों भाई एक स्थान पर नहीं थे। इस वजह से गैंग दो भाई को ही निशाना बना सका। अब क्राइम ब्रांच की टीम लारेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है।

एसीपी क्राइम वरुण दहिया का कहना है कि- गांव खोड़ के दोहरे हत्याकांड मामले में लारेंस बिश्नोई से पूछताछ की जानी है। उसमें उसके गैंग का नाम सामने आया था। गैंग के 20 से अधिक गुर्गे अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उससे पूछताछ में कई अन्य मामलों की भी जानकारी सामने आ सकती है।

ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब मुंबई में क्या होने जा रहा?

ग्रेटर नोएडा स्थित इंटरनेशनल फिल्म सिटी (International Film City) की निविदा को सफल बनाने के लिए यमुना प्राधिकरण (यीडा) अधिकारी मुंबई में रोड शो करेंगे। इसी माह के अंतिम सप्ताह में रोड शो होने की संभावना है। फिल्म जगत के दिग्गजों के साथ बैठक कर उन्हें निविदा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। बोनी कपूर कंगना रनौत अक्षय कुमार आदि फिल्म सिटी का प्रस्तावित साइट का निरीक्षण कर चुके हैं।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित इंटरनेशनल फिल्म सिटी (International Film City) की निविदा को सफल बनाने के लिए यमुना प्राधिकरण (यीडा) अधिकारी मुंबई में रोड शो करेंगे। इसी माह के अंतिम सप्ताह में रोड शो होने की संभावना है।

फिल्म जगत के दिग्गजों के साथ बैठक कर उन्हें निविदा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। बोनी कपूर, कंगना रनौत, अक्षय कुमार आदि फिल्म सिटी का प्रस्तावित साइट का निरीक्षण कर चुके हैं।

पहले भी निकल चुकी हैं दो निविदा

यीडा (YEIDA) के सेक्टर-21 में एक

हजार एकड़ में फिल्म सिटी प्रस्तावित है। प्राधिकरण पूर्व में दो बार निविदा (Film City Tender) निकाल चुका है, लेकिन विकासकर्ता चयन में सफलता न मिलने के बाद नियम शर्तों में बदलाव के बाद तीसरी बार निविदा निकाली गई है।

इसे सफल बनाने के लिए यीडा अधिकारी मुंबई में रोड शो करेंगे। इसमें फिल्म सिटी के निर्माण से जुड़ी कंपनियों, प्रोडक्शन हाउस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। 26 अक्टूबर को फिल्म सिटी के लिए प्री बिड बैठक होगी।

बोनी कपूर ने भी दिखाई रुचि

सोमवार को बोनी कपूर के प्रतिनिधि लाइन प्रोड्यूसर विनोद कुमार बिन्नी ने यीडा सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह से मिलकर परियोजना के बारे में जानकारी ली। बोनी कपूर ने भी फिल्म सिटी परियोजना में रुचि दिखाई है।

कई अभिनेता निविदा में हो सकते हैं शामिल

इसके अलावा बालाजी, केसी बोकाडिया, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अजय देवगन के प्रोडक्शन, हाउस ने भी रुचि दिखाई है। ट्यूलिप कंपनी के साथ यूनिवर्सल व वार्नर स्टूडियो के भी निविदा में शामिल होने की उम्मीद है।

विकासकर्ता को 90 साल के लिए लाइसेंस

फिल्म सिटी को एक हजार एकड़ की बजाए चरणबद्ध विकसित किया जाएगा। पहला चरण 230 एकड़ में तीन साल में पूरा होगा। फिल्म सिटी के विकासकर्ता को 90 लाइसेंस मिलेगा। इसके अलावा आठ साल को विकासकर्ता को राजस्व में छूट रहेगी।

आठ साल बाद फिल्म सिटी के यमुना प्राधिकरण को राजस्व की हिस्सेदारी मिलेगी। 116 करोड़ की फिक्स धनराशि की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। विकासकर्ता को आंतरिक निर्माण कार्य की डिजायन में भी छूट प्रदान की गई है। विकासकर्ता फिल्म सिटी में कम से कम दस एकड़ के भूखंड की सबलीज भी कर सकेगा।

आतंकवाद के प्रति कांग्रेस के नरम होते रुख के पीछे आखिर कारण क्या हैं?

नीरज कुमार दुबे

छात्रों के एक वर्ग ने इजराइल को ''उत्पीड़क'' बताते हुए फलस्तीन के लिए ''स्वतंत्रता'' की मांग करते हुए रैलियां निकालीं, यह तो समझ आता है लेकिन यह समझ से परे है कि देश में दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा क्यों नहीं की? इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के दौरान भारत में कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ फिलस्तीन का। फर्क यह है कि जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वह सड़कों पर नहीं उतर रहे लेकिन जो फिलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं वह सड़कों पर उतर कर रैलियां निकाल रहे हैं, प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं और धार्मिक नारेबाजी कर माहौल को उन्मादी बना रहे हैं। ऐसा तब किया जा रहा है जब भारत का आधिकारिक रुख इजराइल के साथ खड़े रहने का है। जो लोग इजराइल पर आतंकवादी हमला करने वाले हमास का साथ दे रहे हैं या उससे सहानुभूति रख रहे हैं उनको समझना होगा कि यह आतंकवाद को शह देने और 'आ बैल मुझे मार' की कहावत को चरितार्थ करने के समान है।

इसके अलावा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के एक वर्ग ने इजराइल को ''उत्पीड़क'' बताते हुए फलस्तीन के लिए ''स्वतंत्रता'' की मांग करते हुए रैलियां निकालीं, यह तो समझ आता है लेकिन यह समझ से परे है कि देश में दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा क्यों नहीं की? देखा जाये तो कांग्रेस ने फलस्तीनी लोगों की जमीन, स्वशासन और आत्म-सम्मान के साथ जीने के अधिकारों की मांग करके एक तरह से आतंकवाद के साथ खड़े होने का संकेत दे दिया है जिससे वह राजनीतिक रूप से निशाने पर भी आ गयी है। यहां सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इजराइल-हमास संघर्ष पर जो प्रस्ताव पास हुआ कहीं इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहे जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार तो नहीं हैं? सवाल यह भी है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने आतंकवादी हमलों में अपने कई बड़े नेताओं को खोया है वह कहीं देशद्रोह का आरोप झेलने वाले कन्हैया कुमार के बहकावे में आकर तो इस तरह के प्रस्ताव पास नहीं कर रही है? हम कन्हैया कुमार पर सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि वह भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के प्रभारी हैं। इसी संगठन यानि एनएसयूआई की जामिया इकाई ने फलस्तीन का समर्थन करते हुए क्षेत्र में इजराइल की उपस्थिति को ''आतंकवाद'' बताया था। बाद में विवाद होने पर इस पोस्ट को हटा दिया गया था। कांग्रेस की छात्रा शाखा के हटाए गए पोस्ट में लिखा था, ''इजराइल का फलस्तीन पर सात दशक से कब्जा आतंकवाद है। फलस्तीन को इजराइली यहूदीवादी आतंकवाद से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और लंबे समय से जारी इस संघर्ष का न्यायसंगत और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए।'' इसलिए एक बार फिर सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की बदलती विचारधारा के पीछे कन्हैया कुमार ही हैं?

हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस में ऐसे कई और नेता हैं जो समय-समय पर तुष्टिकरण की राजनीति के चलते आतंक के साथ खड़े नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह कर बुलाया था। यही नहीं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के दस साल के राज में आतंकवादियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत कई छोटे-बड़े शहरों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक परिवहन के साधनों को निशाना बना कर सैंकड़ों निर्दोषों की जान ली थी लेकिन सरकार कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाई थी। बल्कि यूपीए के दौर में सरकार से जुड़े लोगों ने आतंक को भगवा रंग देने का प्रयास कर मुद्दे को नया रूप दे डाला था जिसका परिणाम देश को भुगतना पड़ा था। हम आपको

याद दिला दें कि वह यूपीए का ही दौर था जब 26/11 हमले के बाद हम दुश्मन को सबक सिखाने की बजाय उसे सिर्फ डोजियर सौंपने में लगे हुए थे, वह कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए का ही दौर था जब तकनीक के मामले में सरकारी एजेंसियों से आगे आतंकवादी थे, वह यूपीए का ही दौर था जब निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की बजाय कैमरे लगाने के लिए एक विभाग दूसरे विभाग को पत्र ही लिखता रहता था। बहरहाल, देखा जाये तो हम आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का आह्वान भर करते हैं जबकि इस मुद्दे पर हमारे देश में ही विचार बंटे हुए हैं। जो लोग आज हमास के साथ खड़े हो रहे हैं या इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा करने से बच रहे हैं उन्हें समझना होगा कि यह आतंकवाद के प्रति नरम रुख अपनाने जैसा ही है। आज अगर कांग्रेस पार्टी के रुख से ऐसा लग रहा है कि उसे हमास की ओर से इजराइल पर किये गये हमले का कोई दुख नहीं है तो स्लीपर सेलों में बैठे आतंकवादियों का हौसला बढ़ेगा। आज अगर कांग्रेस के रुख से ऐसा लग रहा है कि निर्दोष इजराइलियों की जान जाने का कांग्रेस को कोई गम नहीं है तो दुनिया भर में यही संदेश जायेगा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत दुनिया भर को जो सीख देता है वह कोरा उपदेश है। यदि कांग्रेस ने हमास समर्थक जैसा दिखने का अपना रुख बनाये रखा तो कल को इस पार्टी के सत्ता में आने पर आतंकी तत्व सर उठा सकते हैं। इसलिए जनता को बेहद सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि जो पार्टी आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से कड़ा या नरम रुख दर्शाए वह कभी आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकती।

नई Tata Nexon EV खरीदें या MG ZS EV ?, खरीदने से पहले जानें हर जरूरी बात

टाटा मोटर्स ने 2023 टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है. माना जा रहा है कि यह मॉडल मार्केट में पहले से मौजूद एमजी जेडएस ईवी मॉडल के लिए जबरदस्त टक्कर देगा.

चार पहिया वाहन क्षेत्र में कंपनियां काफी तेजी से अपने इलेक्ट्रिक मॉडल को लॉन्च कर रहे हैं इसी कड़ी में हाल में ही दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स ने 2023 टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया है. इस आर्टिकल में हम 2023 टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट (2023 Tata Nexon EV) और एमजी मोटर की जेडएस ईवी मॉडल (MG ZS EV) की आपस में तुलना करेंगे.

2023 Tata Nexon EV facelift मॉडल का बैटरी पैक

मोटर्स कंपनी ने 2023 टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट मॉडल के दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं पहले वेरिएंट मिड रेंज और दूसरा लॉन्ग रेंज है. इन दोनों वेरिएंट में अलग तरह का बैटरी पैक भी दिया गया है. मिड रेंज में करीब kWh बैटरी पैक दिया गया है जबकि लॉन्ग रेंज में 40.5 kWh का बैटरी पैक दिया गया है.

MG ZS EV मॉडल का बैटरी पैक

एमजी जेडएस ईवी मॉडल के मार्केट में पांच वेरिएंट उपलब्ध है हम केवल एमजी जेडएस ईवी मॉडल कि बात करें तो कंपनी की तरफ से इसमें 50.3 kWh बैटरी पैक की सुविधा दी गई है. रेंज की बात करें तो बैटरी को एक बार चार्ज कर लेने पर यह करीब 461 किलोमीटर की रेंज को टच कर सकता है.

2023 Tata Nexon EV facelift मॉडल का पावर

पावर की बात करें तो 2023 टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट मॉडल में जेन2 मोटर दिया गया है मिड रेंज वेरिएंट की बात करें तो यह करीब 127 बीएचपी अधिकतम पावर और 215 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कर सकता है वही लॉन्ग रेंज वेरिएंट की बात करें तो यह करीब 143 बीएचपी अधिकतम पावर और 215 एनएम टॉर्क जनरेट कर सकता है.

MG ZS EV मॉडल का पावर

एमजी जेडएस ईवी मॉडल के पावर कैपेसिटी की बात करें तो यह मोटर चालू करने पर 174.33 बीएचपी की पावर और 280 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होता है.

भारत में इस महीनें लॉन्च होंगी 7 नई कारें टाटा पंच ईवी से लेक्सस LM एमपीवी तक

भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में अक्टूबर 2023 के महीने में काफी हलचल होने की उम्मीद है, क्योंकि अलग-अलग सेगमेंट में नई कारें लॉन्च होने का इंतजार कर रही हैं। त्योहारी सीजन के चलते कंपनियों ने तगड़ी तैयारी कर रखी है और इस महीने 7 नई कारें भारत में एंट्री मारने को तैयार हैं। आइए इन आगामी मॉडलों के बारे में जान लेते हैं।

1. टाटा पंच ईवी

फेसलिफ्टेड नेक्सन और नेक्सन ईवी के लॉन्च के बाद टाटा मोटर्स द्वारा इस महीने पंच ईवी को पेश करने की उम्मीद है। इसमें ज़िप्ट्रोन तकनीक शामिल होगी और संभवतः इसे दो बैटरी विकल्पों में पेश किया जाएगा। दावा किया गया है कि इसकी ड्राइविंग रेंज लगभग 350 किमी हो सकती है और इसमें अपडेटेड नेक्सन डुओ से प्राप्त बहुत सारे उपकरण और तकनीक के साथ प्रीमियम इंटीरियर होगा।

2. महिंद्रा बोलेरो निओ प्लस

कुछ ही दिन पहले महिंद्रा ने बोलेरो नियो प्लस का एम्बुलेंस वर्जन पेश किया था और इस प्रकार इसका सिबिलियन वर्जन आने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इसे सात और नौ-सीटर कॉन्फिगरेशन में पेश किया जाएगा और इसे 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन के साथ बेचा जाएगा, जिसे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा।

3. निसान मैग्नाइट एएमटी और कूरो स्पेशल एडीशन

निसान इंडिया इस महीने मैग्नाइट सब-फोर-मीटर एसयूवी का कुरो स्पेशल एडिशन लाएगी और इसके साथ एएमटी वर्जन भी होगा। कुरो स्पेशल एडिशन में अंदर और बाहर एक ब्लैक थीम मिलेगी और इसे कई वेरिएंट में बेचा जाएगा।

4. टोयोटा अर्बर क्रूजर टेसर

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का रीबैज वर्जन इस महीने बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकता है और इसका एक्सटीरियर थोड़ा अलग होगा। इंटीरियर लगभग इसके डोनर के समान होगा और इसे पावर देने के लिए 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। ट्रांसमिशन विकल्पों में मैनुअल व ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल होगा।

5. 5-डोर गुरखा

फोर्स गुरखा के कई वेरिएंट पर काम कर रही है और पांच दरवाजों वाला संस्करण मौजूदा मॉडल की तुलना में अधिक व्यावहारिक होगा। इसे मर्सिडीज-बेंज से प्राप्त 2.6 लीटर डीजल इंजन के साथ पेश किया जाना जारी रहेगा।

6. लेक्सस एलएम एमपीवी

लेक्सस एलएम और टोयोटा वेलफायर में काफी समानताएं हैं और भारत में इसकी बुकिंग कुछ महीने पहले शुरू हुई थी। इस महीने कीमतें सामने आने की उम्मीद है और ये चार व सात सीटों वाले लेआउट में उपलब्ध होगी। इसे पावर देने के लिए 2.5 लीटर हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो लगभग 250 एचपी की पावर का उत्पादन करेगा।

आ गया 200 KM की रेंज वाला ई स्कूटर, 3 सेकेंड में पकड़ेगा 40 की रफ्तार, 65 Kmph की टॉप स्पीड

इलेक्ट्रिक वन ने अपने दो नए ई स्कूटर इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं. इलेक्ट्रिक वन ने अपने दो नए ई स्कूटर इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं.

नई दिल्ली. देश में लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ती जा रही है. चलाने में किफायती व लंबे समय तक चलाए जा सकने वाले इन व्हीकल्स को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. कारों के साथ ही बाइक्स और स्कूटर के इलेक्ट्रिक अवतार भी अब देश में लगातार लॉन्च हो रहे हैं. इसी कड़ी में इलेक्ट्रिक वन ने अपना ई 1 एस्ट्रो प्रो सीरीज को लॉन्च किया है. गौरतलब है कि देश में 80 शहरों में कंपनी के 100 से ज्यादा स्टोर्स और सर्विस स्टेशंस हैं. स्कूटर में कंपनी ने शानदार फीचर्स दिए हैं. इसी के साथ इसकी रेंज भी काफी शानदार दी गई है.

जानकारी के अनुसार कंपनी ने अपनी प्रो सीरीज में ई1 ऐस्ट्रो प्रो और ई 1 ऐस्ट्रो प्रो 10 इंडिया में लॉन्च किया है. स्कूटर की कीमत 99,999 रुपये और 1,24,999 रुपये ऑन रोड है. खास बात ये है कि इन दोनों ही स्कूटर्स का पिक अप है. स्कूटर को कंपनी 5 कलर ऑप्शंस में ऑफर कर रही है. इसमें आपको रैड बैरी, ब्लेज ऑरेंज, ऐलीगेंट वाइट, मैटेलिक ग्रे और रेसिंग ग्रीन कलर देखने को मिलेगा.

मिलेगी शानदार रेंज

जानकारी के अनुसार स्कूटर में कंपनी ने 72 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी लगाई है. ये बैटरी 2000 वॉट की मोटर से कनेक्टेड है. स्कूटर की रेंज सिंगल चार्ज पर 200 किलोमीटर की है. वहीं इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटे की है. स्कूटर केवल 2.99 सेकेंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है. वहीं इसको फुल चार्ज करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है.

इन राज्यों में मिलेगा

फिलहाल कंपनी का स्कूटर आपको गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व असम में उपलब्ध होगा. आने वाले समय में कंपनी 20 और शहरों में अपना विस्तार करने जा रही है. भारत के साथ ही कंपनी श्रीलंका और नेपाल में भी अपने शोरूम खोलने जा रही है. फिलहाल कंपनी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, स्पेन, इटली, तुर्कि और इंडोनेशिया में अपने स्कूटर बेचती है. इलेक्ट्रिक वन ऐनर्जी के संस्थापक व सीईओ अमित दास ने कहा कि कंपनी ने मानेसर गुरुग्राम में इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग सैटअप तथा दुनिया के अग्रणी सप्लायरों के साथ गठबंधन किया है. ईवी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और हम ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

घातक हो रहा है विदेशों में पढ़ाई का क्रेज

डा. अश्विनी महाजन

इन युवाओं के पासपोर्ट तक एजेंटों के द्वारा कब्जा लिए जाते थे और उनका तरह-तरह से शोषण भी किया जाता था। उन्हें अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ता था, ऐसे में भारत सरकार द्वारा विविध प्रकार के प्रयासों से समझाने की कोशिश की गई और सरकार ने एजेंटों के पंजीकरण को अनिवार्य किया और विदेशों में जाने वाले भारतीयों के हित संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए

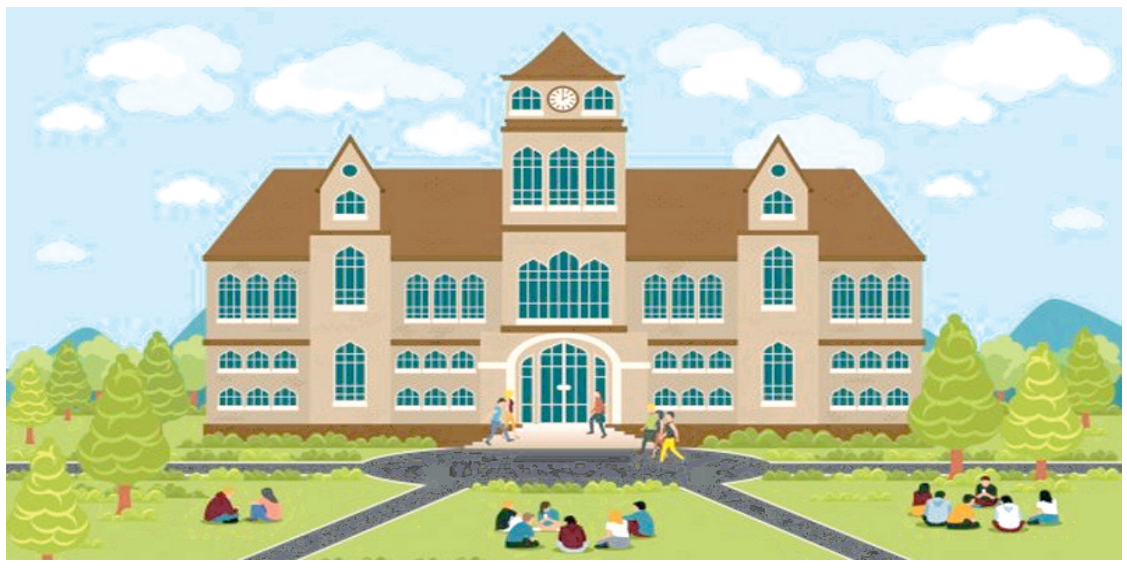

पिछले कुछ वर्षों से भारत से विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर वहीं बसने की आकांक्षा का क्रेज बढ़ता जा रहा है। केन्द्र सरकार के अनुसार वर्ष 2016 और 2021 के बीच 26.44 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढने के लिए गए। एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) का अनुमान है कि वर्ष 2020 में 4.5 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने गए और उन्होंने 13.5 अरब डालर का खर्च किया। वर्ष 2022 में यह खर्च 24 अरब डालर यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए रहा और रेडसियर स्टार्टेजी कन्सलटेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक यह खर्च 80 अरब डालर यानी 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जब अनुमानित 20 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढने के लिए जाएंगे। केन्द्रीय मंत्री बी. मुरलीधरन ने 25 मार्च 2022 को लोकसभा को सूचित किया किया कि वर्तमान में 13 लाख भारतीय विद्यार्थी विदेशों में पढ़ रहे हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के इस वक्तव्य के अनुसार वर्ष 2021 में 4.44 लाख विद्यार्थी विदेशों में पढने गए। एक अन्य सरकारी वक्तव्य के अनुसार नवंबर 30, 2022 तक विदेशों में पढने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6.46 लाख थी, यानी 45 प्रतिशत की वृद्धि। यदि राज्यवार ब्यौरा देखें तो वर्ष 2021 तक विदेशों में पढने जाने वाले विद्यार्थियों में 12 प्रतिशत पंजाब से, 12 प्रतिशत ही आंध्र प्रदेश से और 8 प्रतिशत गुजरात से थे। अगर युवाओं की कुल संख्या के अनुपात में देखा जाए तो पंजाब से प्रत्येक हजार में से 7 युवा, आंध्र प्रदेश में प्रति हजार में 4 युवा और गुजरात से प्रति हजार में से कम से कम 2 युवा विदेशों में हर साल पढने जा रहे हैं। यदि वर्ष 2016 से 2022 की संचयी संख्या लें तो स्थिति काफी भयावह दिखाई देती है।

पंजाब में यह संख्या 50 प्रति हजार, आंध्र प्रदेश में 30 प्रति हजार और गुजरात में 14 प्रति हजार है। विदेशों में पढने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि कई कारणों से चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि ये युवा पढ़ाई और रोजगार की तलाश में विदेशों को पलायन कर रहे हैं और इस कारण देश के समक्ष युवा शक्ति के पलायन की समस्या बढ़ रही है, इससे देश के उद्योग-धंधों के लिए श्रम शक्ति की कमी की समस्या भी आ सकती है। इसके अलावा देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में जा रही है। ऐसा देखने में आ रहा है कि उनके माता-पिता अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर इन युवाओं को विदेशों में पढने के लिए भेज रहे हैं। एक समय था कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के माध्यम से पंजाब के गांवों में बड़ी मात्रा में विदेशों से धन आता था। विदेशों में पढ़ाई के इस क्रेज के चलते यह प्रक्रिया उलट हो गई है, यानी अब विदेशों से धन आने के बजाय विदेशों को धन भेजा जा रहा है। ऐसे में जब वर्ष 2024 तक विदेशों में पढने जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख और उनके द्वाराखर्च की जाने वाली राशि 80 अरब डालर पहुंच जाएगी, तो यह देश के लिए अत्यंत संकटकारी स्थिति का कारण बनेगा।

नहीं है देश में शिक्षा सुविधाओं की कमी : गौरतलब है कि युवाओं का शिक्षा के लिए विदेशों में पलायन, देश में शिक्षा सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं है। वास्तव में देश में पिछले दो-तीन दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। यदि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का प्रवेश देखें तो 1990-91 में जहां मात्र 49.2 लाख विद्याार्थियों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया, यह संख्या वर्ष 2020-21 में 414 लाख तक पहुंच गई। मोटे तौर पर उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्याार्थियों की संख्या पिछले 30 वर्षों में 10 गुणा से भी ज्यादा हो चुकी है। यदि उच्च शिक्षा संस्थानों की बात की जाए तो देखते हैं कि वर्ष 2021 में देश में 1113 विश्वविद्यालय और समकक्ष संस्थान, 43796 महाविद्यालय और अन्य स्वतंत्र संस्थान 11296 थे। इसी वर्ष देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में 15.51 लाख शिक्षक कार्यरत थे। देश में कई विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और कई अन्य राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में निजी विश्वविद्यालय हैं और कई 'विश्वविद्यालय सम' यानी 'डीम्ड विश्वविद्यालय' हैं। देश में कई विश्वस्तरीय प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जिनसे शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी वैश्विक कंपनियों में उच्च पदों पर आसीन हैं। जहां तक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए फीस का सवाल है, अधिकांश भारतीय शिक्षा संस्थानों में फीस विदेशी संस्थानों में फीस से कहीं कम है और जिन विदेशी संस्थानों में भारतीय युवा प्रवेश ले रहे हैं, उनमें से अधिकांश का स्तर अत्यंत नीचा है। तो सवाल उठता है कि भारी भरकम राशि खर्च कर भारत के युवा विदेशी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश क्यों लेते हैं? इसका सीधा उत्तर यह है कि विदेशों में जाने वाले अधिकांश विद्यार्थी उच्च स्तरीय शिक्षा में प्रवेश लेकर वास्तव में कोई उच्च स्तरीय डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आस्ट्रेलिया, कनाडा, और यहां तक कि इंग्लैंड समेत अन्य यूरोपीय देशों में जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों का वास्तविक लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना नहीं, बल्कि वहां रोजगार प्राप्त करना है। लेकिन भारतीय युवा यह समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि इन देशों में भी रोजगार की भारी कमी है। कई देशों में वहां के स्थानीय लोग भारतीय एवं अन्य देशों से आने वाले युवाओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें भी देखने को मिल रही हैं। देश से जाने वाले अधिकांश युवा विद्यार्थी वहां रोजगार प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं और उन्हें स्वदेश वापस लौटना पड़ता है, जिसके कारण वे भारी कुंठा का भी शिकार हो रहे हैं।

विदेश जाने के क्रेज को थामने की जरूरत : चूंकि व्यक्तिगत तौर पर विदेशों में जाने वाले युवा विद्यार्थी पूर्व में विदेशों में जाने वाले भारतीयों की सफलता की गाथाओं से प्रभावित होकर विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन वे यह समझ नहीं पा रहे कि आज कनाडा, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में, जहां वे शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं, वे शिक्षा संस्थान स्वयं के अस्तित्व को बचाने हेतु भारतीय विद्यार्थियों को आसानी से अपने शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दे रहे हैं। यही नहीं, भारतीय और अन्य देशों के अति इच्छुक विद्यार्थियों से भारी फीस ऐंठने हेतु शिक्षा की कई दुकानें भी खुल रही हैं, जिनका वास्तविक शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है।

ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकारों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं को इस हेतु वास्तविकता से अवगत कराने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है, ताकि वे विदेशों में जाकर अपने माता-पिता की गाढ़ी कमाई को यूं ही न गंवा दें। गौरतलब है कि पिछले लगभग दो दशकों से भारत के कई नागरिक एजेंटों के माध्यम से विदेशों में, खास तौर पर खाड़ी के देशों में रोजगार की तलाश में गए और वहां उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन युवाओं के पासपोर्ट तक एजेंटों के द्वारा कब्जा लिए जाते थे और उनका तरह-तरह से शोषण भी किया जाता था। उन्हें अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ता था, ऐसे में भारत सरकार द्वारा विविध प्रकार के प्रयासों से समझाने की कोशिश की गई और सरकार ने एजेंटों के पंजीकरण को अनिवार्य किया और विदेशों में जाने वाले भारतीयों के हित संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए। इसी तर्ज पर देश के अनभिज्ञ युवा जो विदेशों में शिक्षा के नाम पर ठगे जा रहे हैं, उन्हें इस समस्या से बचाने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी आगे आना होगा।

संपादक की कलम से

एक शाश्वत युद्ध

यह एक देश ने दूसरे देश के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा है। फिलस्तीन की गाजा पट्टी के अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन 'हमास' ने संप्रभु, स्वायत्त देश इजरायल पर अचानक आतंकी हमला किया है। हमास इजरायल के प्रति नफरत और दुश्मनी की हद तक सोचता है, लिहाजा उसके अस्तित्व को ही मान्यता नहीं देता। यह युद्ध कहां तक खिंचेगा, अभी आकलन करना मुश्किल है, लेकिन इजरायल ने इस हमले को 'युद्ध' करार देते हुए पलटवार किया है। नतीजतन गाजा पट्टी में विध्वंस जारी है। हमास इजरायल पर हमला कर बहुत कुछ तबाह कर चुका है। हैवानियत की हद तक उसके लड़ाके चले गए हैं। हमास ने जिन्हें बंधक बना कर गाजा की सुरंगों में रखा है, वह उन्हें मानव-ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। दोनों पक्षों के 1000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। घायलों की संख्या 4000 से ज्यादा बताई जा रही है। इजरायल ने हवाई हमले कर गाजा पट्टी में हमास के 426 ठिकानों को 'मलबा' बना दिया है। इजरायल के कुछ सैन्य अधिकारी 800 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा कर रहे हैं। उनमें रिहायशी इलाके, अस्पताल, स्कूल, बाजार भी शामिल हैं। गाजा करीब 23 लाख की आबादी वाला सबसे घना इलाका है, लिहाजा नुकसान और मौतें भी उसी अनुपात में होंगी। आखिर इजरायल वहां कितने हमले करेगा, क्योंकि गाजा के बाद अन्य देशों की सीमाएं शुरू होती हैं।

बहरहाल इस अचानक, अप्रत्याशित युद्ध ने दुनिया के प्रमुख देशों को दो हिस्से में विभाजित कर दिया है। हालांकि हमास एक आतंकी संगठन है, जिसकी ताकत 50,000 से अधिक लड़ाके हैं, लेकिन ईरान, लेबनॉन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, ओमान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि इस्लामी देश हमास का समर्थन कर रहे हैं। वे उसकी फंडिंग भी करते हैं। दूसरी तरफ भारत समेत अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, यूरोपीय देशों ने हमास के इजरायल पर हमले को '9/11 जैसा आतंकी हमला' करार दिया है और उसकी निंदा भी की है। भारत इजरायल के साथ खड़ा है, लेकिन उसने फिलिस्तीन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। भारत के 18,000 से अधिक छात्र और कामगार, पर्यटक आदि इजरायल में हैं। फिलहाल सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उनकी सकुशल वापसी के प्रयास शुरू हो चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री दफ्तर इस अभियान की निगरानी कर रहा है। दरअसल अमरीका ईरान, सऊदी अरब और इजरायल की 'दोस्ती' कराने की मध्यस्थता कर मध्य-पूर्व की परिभाषा ही बदल देना चाहता था। उसका हमास, हिजबुल्लाह सरीखे आतंकी संगठन और कुछ अन्य देशों ने जमकर विरोध किया। अरब की दुनिया और यहूदियों के देश इजरायल के बीच एक शाश्वत वैमनस्य रहा है। विरोध और जंगों का लंबा अतीत है।

दरअसल इजरायल में शनिवार को छुट्टी थी और अधिकतर लोग 'यहूदी उत्सव' के मूड में थे। सैनिक भी छुट्टी लेकर गए थे। ऐसे में हमास के लड़ाकों ने घुसपैठ की और इजरायल पर 5000 रॉकेट भी दागे गए। हवा, जमीन, समंदर से एक साथ अचानक हमले ने इजरायल को स्तब्ध कर दिया और दुनिया चौंक उठी। यदि बीते डेढ़ साल से गाजा पट्टी में खामोशी थी और हमास भी अपेक्षाकृत शांत था, तो इजरायल की विख्यात खुफिया एजेंसी 'मोसाद' और परम मित्र अमरीका की 'सीआईए' और सेटेलाइट प्रणालियों को आतंकी हमले की तैयारियों की भनक तक क्यों नहीं लगी? यह इजरायल की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा सवाल और धब्बा है। यह बहुत बड़ी नाकामी भी है, जिस पर मंथन किया जा रहा होगा! सवाल यह भी है कि हमास के पास मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, बम, टैंक आदि सैन्य हथियार इतनी संख्या में कहां से आए, जिनके सहारे एक जंग लड़ी जा सके?

राय

नए पर्यटन की पैदावार

पर्यटन से मुलाकात करतीं योजनाएं अब एडीबी फंडिंग के तहत मुस्करा रही हैं और इस दृष्टि से कुल 2300 करोड़ के प्रस्तावों में से 1313 करोड़ की मंजूरी, बरसाती आपदा के बाद अपनी क्षमता को फिर से उगाने का सबब बनेगी। वर्तमान सुक्खू सरकार के इरादों के फलक पर पर्यटन का मकसद जिस आर्थिकी को पुकार रहा है, उसे कुछ हद तक एशियन डिवेलपमेंट बैंक ने सुना और प्रोजेक्ट के पहले चरण के बिड डाक्यूमेंट को मंजूर कर दिया। जाहिर है इससे धर्मशाला कान्वेंशन सेंटर, दियोटसिद्ध मंदिर परिसर और पालमपुर शहर के परिदृश्य में सौंदर्यीकरण से पर्यटन सुदृढ़ होगा। एडीबी की मदद से पर्यटन की अन्य अनेक मीनारें भी खड़ी होनी हैं और अगर यह प्रक्रिया मुकम्मल होती है, तो गुणात्मक दृष्टि से यह क्षेत्र कुछ नए मील पत्थर रख पाएगा। ऐसा नहीं है कि पर्यटन के हिस्से पहले कम फंड आया, लेकिन कुछ परियोजनाएं केवल सियासी मंसूबों के खातिर दफन हो गईं। कई ऐसी संपत्तियां या चौबारे खड़े हो गए, जो पर्यटन के नाम पर अपनी प्रासंगिकता दर्ज नहीं कर पाए। सार्वजनिक उपक्रम हिमाचल पर्यटन विकास निगम को घाटा उठाना पड़ रहा है, तो इसके परिसरों के बेहतर इस्तेमाल की एक नई कड़ी बनानी होगी। मसलन हर शहर के किसी न किसी बाजार को पर्यटन बाजार की अहमियत में विकसित करें, तो हिमाचल का खान पान और उपहार सारे देश में पहुंच जाएंगे। इसके लिए शहरी व ग्रामीण निकायों को बाध्य किया जाए कि ये अपने संसाधनों से प्रदेश के पर्यटन नक्शे में इजाफा करें। बहुत पहले मंडी शहर में पंडित सुखराम ने इंदिरा मार्केट की परिकल्पना में एक ऐसा अद्भुत संसार रचा कि यह स्थान रौनक, रोमांच और व्यापार की अनिवार्यता में मनोरंजन सरीखा हो गया। विडंबना यह है कि हमने शिमला के मॉल और गेयटी थियेटर के पर्यटन महत्त्व का प्रदेश में प्रसार नहीं किया। कमोबेश हर शहर, पर्यटन डेस्टिनेशन और धार्मिक स्थल को सुकून की राहें-चरागाहें चुननी चाहिएं और इसके लिए वाहन वर्जित मार्केट, बड़े मैदान और ईको टूरिज्म के निशान बढ़ाने होंगे। पिछले दशक में हमीरपुर शहर के मुख्य बाजार को वाहन वर्जित माल रोड बनाने की मांग उठी, लेकिन जिन्हें अफरातफरी में व्यापारिक हित नजर आता है, वे इसके सियासी विरोध पर उतर आए। धर्मशाला का कोतवाली बाजार यह नहीं चाहता कि वाहन बाइपास से गुजर जाएं और कुछ इसी तरह के असमंजस में शाहपुर बाजार प्रस्तावित फोरलेन से उलझ रहा है। प्रमुख बाजारों को मालरोड बनाने के लिए एडीबी फंडिंग के बजाय इच्छाशक्ति चाहिए। अगर एक प्वाइंट से इलेक्ट्रिक कार्ट प्रमुख बाजारों को चलें और बाजार से पहले महापार्किंग में वाहन आगमन थमे, तो हिमाचल के कई शहर पर्यटकों के लिए भी कनाट प्लेस या चंडीगढ़ के सत्रह सेक्टर जैसा माहौल पैदा कर सकते हैं। इसी तरह एडीबी की मदद के बिना सार्वजनिक परिवहन के साथ पर्यटन परिवहन के विकल्प जोड़े जाएं, तो हर शहर का मंजर कुछ और होगा। प्रदेश को छोटे-बड़े बस अड्डों के प्रारूप में सुधार करते हुए, इन्हें निजी पार्टनरशिप में निखारना चाहिए, ताकि ये स्थल भविष्य की महापार्किंग, मनोरंजन व व्यापारिक केंद्र के रूप में सिटी सेंटर भी बनें। ऐसे में एचआरटीसी के साथ-साथ, मिल्क फेडरेशन, एचपीएमसी व कुछ अन्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के सहयोग से बस स्टैंड के पते पर पर्यटक को हिमाचल से रू-ब-रू कराने का मंतव्य पूरा कर सकते हैं। हमारा मानना है कि अगर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के साथ एक खेल, सांस्कृतिक व व्यापारिक परिसर खड़ा किया जाए, तो हर दिन वहां सारे हिमाचली उत्पादों के उपहार, कलाओं के प्रदर्शन, पर्यटन केंद्रों के दर्शन तथा यात्रा के नए डेस्टिनेशन का प्रचार किया जा सकता है। इस दिशा में मंडी व शिमला के प्रस्तावित खादी प्लाजा निश्चित रूप से एक आशातीत संकल्प हैं।

श्राद्ध कर्म की उपयोगिता एवं व्यावहारिकता

प्रो. सुरेश शर्मा

अपने पूर्वजों के सम्मान तथा उनकी आत्मिक शांति के लिए श्रद्धा का प्रतीक श्राद्ध अवश्य करें, परन्तु जीते जी उनसे प्रेम करें, उनका सम्मान करें, उन्हें सुख-शान्ति प्रदान करें। श्राद्ध कर्म का फर्ज निभाते हुए वृद्धों का दर्द भी महसूस करने का प्रयास करें। यह श्राद्ध कर्म सामाजिक रूप से पीढियों की सुख-शांति के लिए आवश्यक है, वहीं पर सही अर्थों में इसकी व्यावहारिकता को समझने की आवश्यकता है। मूल्यों की रक्षा करते हुए जीवित प्रियजनों के लिए सेवा, आदर एवं श्रद्धा का भाव रखें'

भारतीय हिन्दू संस्कृति एवं परम्परा के अनुसार श्राद्ध का अभिप्राय श्रद्धा से है, इसलिए हर वर्ष पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों को याद करते श्राद्ध कर्म किया जाता है। प्रत्येक वर्ष पितरों की प्रसन्नता, दुःखों से मुक्त होने का पर्व श्राद्ध 16 दिनों तक मनाया जाता है। प्रत्येक परिवारजन मृत्युतिथि पर श्राद्ध, पिंडदान, जलदान आदि करके पितरों को तृप्त करते हैं। सनातन धर्मावलंबियों द्वारा पितरों की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि करना आवश्यक समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने से कुल में वीर, निरोगी, शतायु एवं श्रेय प्राप्त करने वाली संततियां उत्पन्न होती हैं। श्राद्ध करने से वृद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धरणा शक्ति, पुत्र-पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। भारतीय संस्कृति में पुत्रों या पौत्रों द्वारा पितरों के प्रति श्रद्धा तथा आस्था रखते हुए उनकी मुक्ति, सद्गति तथा शांति के लिए श्राद्ध कर्म करने का उत्तरदायित्व निभाना एक सभ्य, संस्कारी तथा जिम्मेदार मनुष्य की निशानी समझा जाता है।

श्राद्ध का अर्थ श्रद्धापूर्वक किया हुआ वह संस्कार जिससे पितर संतुष्टि प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है जो अमावस्या तक रहता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिजनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मानवीय मूल्यों पर विचार करते हुए यह ठीक भी है कि हमें पारिवारिक जड़ों को याद रखते हुए अपने पूर्वजों के लिए आदर एवं सम्मान व्यक्त करना चाहिए। धार्मिक संस्कारों तथा सामाजिक परम्पराओं को जीवित रखते हुए यह आवश्यक भी है। संस्कृति तथा परम्पराओं का सम्मान करते हुए व्यक्ति को कुछ आवश्यक बातों पर गम्भीरतापूर्वक भी विचार करना चाहिए। वर्ष में एक बार पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के समय अपने पूर्वजों तथा माता-पिता का कुत्ते, कौवे, गाय तथा भिखारी में अपने प्रियजनों का अक्स देखने वालों को यह याद रखना चाहिए कि हमने अमुक व्यक्ति के साथ उसकी मजबूरी, बीमारी तथा उसके जीते जी कैसा व्यवहार किया है? रूढ़िवादी परम्पराओं में लिप्त तथा आडम्बर करते हुए अपने भावों की अभिव्यक्ति का कोई लाभ नहीं होता। यदि हमने किसी व्यक्ति के साथ समय रहते अच्छा व्यवहार नहीं किया हो, उसका दुःख-दर्द महसूस न किया हो, मृत्युपरांत मात्र लोक लाज के लिए दिखावा एवं ढकोसलेबाजी करना कहां तक सही है? वर्तमान समाज में अपने माता-पिता तथा बुजुर्गों के साथ अपमान, अत्याचार, बदतमीजी तथा मारपीट करने की बहुत सी घटनाएं सामने आ रही हैं। घर के पालतू कुत्ते बुजुर्गों से अधिक प्रिय एवं सम्मानीय हो चुके हैं। घर में तकलीफ, लाचारी, बीमारी से ग्रसित वृद्ध रात भर कराहता रहता है।

भोजन, पानी तथा दवाई के लिए तरसता रहता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। संस्कार रहित युवा तथा घर के बच्चे भी उसकी उपेक्षा करते हुए बदतमीजी करते हैं। समाज में असहाय वृद्धों को घरों के भीतर मारपीट तथा प्रताड़ित किया जाता है। फिर मरने के बाद पितृ कर्म से पुण्य प्राप्त करने का आडम्बर करते हैं। ऐसे निष्ठुर तथा क्रूर लोगों को तो जन्मजन्मांतर तक भी सुख-शांति तथा चैन नहीं मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को तो सामाजिक तथा कानूनी दृष्टि से अपराधी घोषित किया जाना चाहिए। वर्तमान समाज में वृद्ध आश्रम का खुलना विकास की निशानी समझा जा रहा है, लेकिन यह हमारी बुद्धि एवं सोच का दिवालियापन है। हालांकि किसी मजबूर एवं लाचार व्यक्ति के लिए ये वृद्धाश्रम वरदान भी साबित हुए हैं। कड़वा सच यह है कि समाज में अधिकतर वृद्ध अपनी ही औलादों के निकृष्ट एवं असंवेदनशील व्यवहार से कुंठित एवं ग्रसित हैं। घरों में वृद्धों को रखने तथा उनकी रोजाना भोजन व्यवस्था पर बेटों और बहुओं को आमतौर पर लड़ते-झगड़ते तथा हिसाब-किताब करते देखा गया है। अनेकों बड़े सम्भ्रांत परिवारों, पढ़े-लिखे, राजनेताओं, व्यापारियों तथा आला अधिकारियों के घरों में यह जगजाहिर तथा खुला सत्य है। यह बहुत ही गंभीर एवं विचित्र स्थिति है। ऐसे में विचार करने योग्य है कि मरने के चार वर्षों के उपरांत यदि किसी मृत आत्मा को श्राद्ध तिथि के अवसर पर पूड़ी, खीर, पकवान, फल, मेवे तथा वस्त्र मिल भी जाएं तो किस काम के? वृद्धाश्रम में रहने वाले उपेक्षित वृद्धों का मानना है कि जीते जी उनकी संतानें कपड़े, दवाई तथा खाने को भोजन नहीं देती तथा मरने के बाद लोकलाज के लिए श्राद्ध, पिंडदान तथा तर्पण का दिखावा करते हैं। अभी हाल ही में कानपुर के रेडियोलॉजिस्ट डॉ. प्रेम साहनी का बेटा उनकी मृत्यु पर कनाडा से घर नहीं पहुंच पाया।

उल्लेखनीय है कि डॉ. साहनी अपने आवासीय परिसर में हृदयघात या फिर कोई जहरीला पदार्थ निगलने से मृत पाए गए थे। चण्डीगढ़ निवासी उनकी बहन डॉ. डेजी तथा डॉ. संजीव ने उन्हें मुखाग्नि दी तथा उनके बेटे को वीडियो कॉल से अन्तिम दर्शन करवाए गए। समाज को आधुनिक, व्यावसायिक तथा भौतिकवादी इन विचित्र स्थितियों पर गम्भीरता से विचार करना होगा। अपने पूर्वजों के सम्मान तथा उनकी आत्मिक शांति के लिए श्रद्धा का प्रतीक श्राद्ध अवश्य करें, परन्तु जीते जी उनसे प्रेम करें, उनका सम्मान करें, उन्हें सुख-शान्ति प्रदान करें। श्राद्ध कर्म का फर्ज निभाते हुए वृद्धों का दर्द भी महसूस करने का प्रयास करें। यह श्राद्ध कर्म सामाजिक रूप से पीढियों की सुख-शांति के लिए आवश्यक है, वहीं पर सही अर्थों में इसकी व्यावहारिकता को समझने की आवश्यकता है। मानवीय, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए मृत प्रियजनों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करते हुए जीवित प्रियजनों के लिए सेवा, आदर एवं श्रद्धा का भाव रखें।

प्रो. सुरेश शर्मा

झूला झूलें पिंग लाल

देश में आजकल बारहमासी सावन के जिन झूलों का रिवाज है, उनमें रस्सी भी चीन की है और पटरा भी। लेकिन मुझे इस बात की पूरी तसल्ली है कि कम से कम पेड़ मेड इन इण्डिया हैं। जब तक देश में दरख्त हैं, तब तक हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हम न सिर्फ मेक इन इण्डिया का आवाहन करते हैं बल्कि अपने देश में पेड़ भी बनाते हैं और उन पर झूले भी डालते हैं। पर दुःख है तो केवल इस बात का कि इन झूलों पर चीन झूल रहा है और हमें कहना पड़ रहा है कि 'झूला झूलें पिंग लाल (शी जिनपिंग)'। जिनके हाथ में झूलों की रस्सियाँ हैं, वे शी जिनपिंग को गलबहियाँ डालने के बाद उसके साथ झूला झूलते हैं और बेचारा विकास ज़मीन पर पड़ा दर्द से बिलबिलाता रहता है। झूले की रस्सी थामने वाले ने साबरमती में जिनपिंग को चीन में बने स्टेंड, रस्सी और पटरे पर झूला झुलवाया था। जिनपिंग मेड इन इण्डिया पेड़ देखकर नाराज़ न हो जाएं, इसलिए झूले को पेड़ पर भी नहीं डलवाया गया। सच्ची दोस्ती की यही निशानी है कि जिसके साथ की जाए, उसे पूरी शिद्दत से निभाया जाए। देश का क्या, वह तो चीन में बनी रस्सी, पटरे और स्टेंड की तरह कहीं भी बनाया जा सकता है। वैसे भी जब चीन ने लद्दाख और अरुणाचल में अपने तम्बू तानने के बाद गाँव बसा ही लिए हैं तो उसे देश के बाक़ी हिस्सों में पहुँचने से भला कौन रोक सकता है। हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर अकाट्य तर्क पेश करते हैं कि सवाल कॉमन सेंस का है। चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम छोटी। क्या किसी छोटी अर्थव्यवस्था को बड़ी अर्थव्यवस्था से पंगा लेना चाहिए। क्यूबा और फिदेल कास्त्रो की बात और है कि उसने आकार और अर्थव्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने चिंदी होने के बावजूद उससे हार नहीं मानी।

अमेरिका झल्लाता रहा, पर कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फिदेल कास्त्रो की तरह दाढ़ी रखने का मतलब यह तो नहीं कि हमारे परिधान मंत्री शी जिनपिंग से भिड़ जाएं। फिदेल कास्त्रो ने कभी अपनी छाती का नाप नहीं बताया। कम से कम हमारे परिधान मंत्री अपने सीने का नाप तो बताते हैं। भले उनके कपड़े का नाप लेने वाला दरजी कहता रहे कि उनकी छाती का नाप तैंतालीस इंच है। पर दावा तो दावा है। वादे और दावे में केवल अक्षर ही आगे-पीछे हैं। लेकिन दोनों की ज़ात तो एक है। पर ऐसा भी नहीं कि चीन का झूला डाल पर ही पड़ा दीखे या किसी चीनी स्टेंड पर। उन पत्रकारों और न्यूज़ हाऊस से पूछ कर देखिए, जिनके गले में आजकल ईडी के झूले पड़े हैं। राष्ट्रपिता की जंयती के अगले दिन सुबह-सवेरे जब चार दरजन से अधिक ये हजरात अभी अपनी हाजत भी नहीं उतार पाए होंगे कि ईडी ने उनके गले में झूले डाल दिए।

चीन से जिन भारतीयों के सीधे व्यापारिक सम्बन्ध हैं, जो चीनी कम्पनियाँ सीधे भारत में निवेश कर रही हैं या जिन चीनी कम्पनियों ने पीएम केयर फंड में भारत में अपने व्यापारिक हितों की पैरवी के लिए खरबों का निवेश किया था, उन्हें छोड़ कर ईडी ने ऐसे न्यूज़ हाऊस पर छापा डाला, जिसे अमेरिका निवासी किसी साम्यवादी विचारधारा के समर्थक रिटायर उद्योगपति ने करीब दस करोड़ का चंदा दिया था। आजकल भारत में बीजे पार्टी की सरकार जिस तरह ईडी का उपयोग कर रही है, उससे मुझे युँगाडा के तानाशाह ईदी अमीन की बड़ी याद आ रही है। ईडी और ईदी में केवल ड और द का फर्क है। लेकिन अपने विरोधियों को गले लगाने का दोनों का तरीका एक सा है। ईदी का हश्र तो पूरी दुनिया जानती है। पर ईडी पर कोई फर्क नहीं पडने वाला। अगली सरकार जिसकी होगी, वह भी अपने विरोधियों के गले में इसी तरह से ईडी की गलबहियाँ डलवाएगी। ईडी न भी हो तो किसी लोकतांत्रिक सरकार के पास उसके चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाने वालों पर देशद्रोह की धाराएं लगाने का अधिकार तो बनता ही है।

पीए सिद्धार्थ

एचडीएफसी के ग्राहकों की ईएमआई में होगी बढ़ोतरी, बैंक ने एमसीएलआर की दर में किया इजाफा

HDFC Bank की ओर से कुछ चुनिंदा अवधि की एमसीएलआर में बढ़ोतरी की गई है। एचडीएफसी बैंक की ओर से ओवरनाइट एमसीएलआर की दर को घटाकर 8.60 प्रतिशत कर दिया गया है। एक महीने का एमसीएलआर 8.65 प्रतिशत कर दिया गया है। तीन महीने का एमसीएलआर 8.85 प्रतिशत और छह महीने का एमसीएलआर 9.10 प्रतिशत कर दिया गया है।

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक की ओर से कुछ चुनिंदा अवधि के एमसीएलआर की दर को 10 आधार अंक बढ़ा दिया गया है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, नई दरें 7 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी हो गई है।

HDFC Bank के लोन की ब्याज दरों में हुआ बदलाव

एचडीएफसी बैंक की ओर से ओवरनाइट एमसीएलआर की दर को घटाकर 8.60 प्रतिशत कर दिया गया है। एक महीने का एमसीएलआर 8.65 प्रतिशत कर दिया गया है। तीन महीने का एमसीएलआर 8.85 प्रतिशत और छह महीने का एमसीएलआर 9.10 प्रतिशत कर दिया गया है।

एक वर्ष का एमसीएलआर जो कि कई ग्राहकों के होम लोन से जुड़ा हुआ होता है। अब 9.20 प्रतिशत हो गया है। वहीं, दो वर्ष का एमसीएलआर 9.20 प्रतिशत है। तीन वर्ष का एमसीएलआर 9.25 प्रतिशत हो चुका है।

क्या होता है MCLR ?

MCLR वह न्यूनतम दर होती है जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को लोन देते हैं। इसी के आधार पर तय किया जाता है कि होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन के लिए ब्याज दर क्या होगी।

एचडीएफसी बैंक ने एफडी पर कम किया ब्याज

एचडीएफसी बैंक की ओर से कुछ चुनिंदा अवधि की एफडी पर ब्याज दरों में कटौती की गई है। बैंक द्वारा 7 दिनों से लेकर 10 वर्षों की एफडी पर 3 प्रतिशत से लेकर 7.20 प्रतिशत का ब्याज सामान्य नागरिकों को दिया जा रहा है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को 3.5 प्रतिशत से लेकर 7.75 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है। आपको बता दें, आरबीआई की ओर से नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया गया था। इसमें रेपो रेट को यथावत रखा गया था।

आरबीआई का बैंक ऑफ बड़ौदा पर बड़ा एक्शन

लाखों ग्राहक होंगे प्रभावित, पढ़िए क्या है पूरा मामला

भारतीय रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण नियामक चिंताओं का हवाला देते हुए आज बैंक ऑफ बड़ौदा पर अपने बॉब वर्ल्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से नए ग्राहक जोड़ने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा कि इस प्रतिबंध के बाद मौजूदा ग्राहकों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। पढ़िए क्या है पूरी खबर।

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा को मटेरीयल सुपरवाइजरी कंसर्न (material supervisory concerns) का हवाला देते हुए बैंक को अपने मोबाइल एप्लिकेशन 'बॉब वर्ल्ड' पर नए ग्राहकों को शामिल करने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।

आरबीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा को 'बॉब वर्ल्ड' मोबाइल एप्लिकेशन पर अपने ग्राहकों की आगे की प्रविष्टि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है।

आरबीआई ने क्यों लगाई रोक ?

आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई ग्राहकों को एप्लिकेशन पर शामिल करने के तरीके में देखी गई कुछ मटेरीयल सुपरवाइजरी कंसर्न पर आधारित है।

बयान जारी करते हुए आरबीआई ने कहा कि

'बॉब वर्ल्ड' एप्लिकेशन पर बैंक के ग्राहकों की आगे की भागीदारी आरबीआई की संतुष्टि के अनुसार देखी गई कमियों के सुधार और बैंक द्वारा संबंधित प्रक्रियाओं को मजबूत करने के अधीन होगी।

मौजूदा ग्राहकों को ना हो कोई परेशानी

आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि मौजूदा 'बॉब वर्ल्ड' ग्राहकों को इस निलंबन के कारण किसी भी व्यवधान का सामना नहीं करना पड़े।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया ब्याज दर

बैंक ऑफ बड़ौदा ने तीन साल तक की विभिन्न अवधि के लिए एफडी ब्याज दरों में 50 आधार अंक (बीपीएस) की बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि बैंक कि ये नई दरें 2 करोड़ रुपये से कम की एफडी के लिए 9 अक्टूबर 2023 से लागू है।

नई ब्याज दर लागू करने के बाद, बैंक अब अपने ग्राहकों को 2-3 साल के लिए 7.25 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को इसी अवधि के लिए 7.75 प्रतिशत तक ब्याज मिल रहा है। ब्याज दर की बढ़ोतरी से मौजूदा ग्राहकों को भी फायदा होगा।

इनसाइड

घर खर्च के साथ आप भी कर सकती हैं अच्छी खासी बचत, फॉलो करें ये आसान टिप्स

आज के समय कमाने के साथ-साथ सेविंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम सही समय पर पैसे सेव नहीं करते हैं तो हमें भविष्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज हम कामकाजी महिला के साथ घरेलू महिलाओं को भी बताएंगे कि वो किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर सकती है।

नई दिल्ली। हर महिला कोशिश करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करें। कई महिला पैसे सेव करने की कोशिश तो करती है पर उनसे पैसे सेव नहीं हो पाते हैं। अगर आप भी पैसे सेव करना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताते जिसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर पाएंगे। हमारे पास जब एक लक्ष्य होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर पाते हैं। ऐसे में आप भी एक फाइनेंशियल गोल बना सकते हैं। यह गोल आपके रिटायरमेंट के बाद की इनकम का हो सकता है या फिर कहीं घूमने को लेकर भी हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि आपको लद्दाख जाना है तो आप उसके लिए अभी से पैसे सेव कर सकते हैं। आपको हर महीने का एक बजट बनाना चाहिए। जब देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें बजट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी तरह घर के खर्चों को पूरा करने और पैसे की बचत करने के लिए भी बजट की जरूरत पड़ती है।

सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन आई तेजी; जानिए क्या है गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट रेट्स

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 0.39 प्रतिशत या 7.30 डॉलर प्रति औंस बढ़कर 1871.75 डॉलर प्रति औंस पर बना हुआ है। दिल्ली में 24 कैरेट का सोना 58680 रुपये और 22 कैरेट का सोना 53800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

नई दिल्ली। सोने में मंगलवार के कारोबारी सत्र में तेजी देखी जा रही है। 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 330 रुपये बढ़कर 58,530 रुपये हो गया है। 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने का मूल्य 53,650 रुपये है। चांदी की कीमत 72,600 रुपये प्रति किलो है।

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में सोने की कीमत

दिल्ली में 24 कैरेट 58,680 रुपये; 22 कैरेट 53,800 रुपये

मुंबई में 24 कैरेट 58,530 रुपये; 22 कैरेट 53,650 रुपये

कोलकाता में 24 कैरेट 58,530 रुपये; 22 कैरेट 53,650 रुपये

चेन्नई में 24 कैरेट 58,690 रुपये; 22 कैरेट 53,800 रुपये

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 0.39 प्रतिशत या 7.30 डॉलर प्रति औंस बढ़कर 1,871.75 डॉलर प्रति औंस पर बना हुआ है। चांदी की कीमत में गिरावट देखी जा रही है और यह 0.08 प्रतिशत या 0.017 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 21.913 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। सोने की कीमत में तेजी की वजह बढ़ती वैश्विक अस्थिरता को माना जा रहा है, जिस वह से सोने की कीमत बढ़ रही है।

वायदा बाजार में सोने-चांदी की कीमत

वायदा बाजार में सोने की कीमत में आज तेजी जारी है। एमसीएक्स पर दिसंबर वायदा के कॉन्ट्रैक्ट्स में 10 ग्राम सोने की कीमत 47 रुपये बढ़कर 57,619 रुपये हो गई है। जानकारों का कहना है कि नई फ्रैश पॉजीशन बनने के कारण वायदा में सोने की कीमत में तेजी आई है।

चांदी की कीमत में गिरावट आई है। दिसंबर के चांदी कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत 227 रुपये या 0.33 प्रतिशत गिरकर 68,867 रुपये प्रति किलो हो गई है।

म्यूचुअल फंड में सिप या लंपसंप क्या है निवेश करने का सही तरीका, समझें दोनों के फायदे और नुकसान

Mutual Funds में एसआईपी या लंपसम कैसे निवेश करना चाहिए। इसके लेकर निवेशकों के मन में कन्फ्यूजन बना रहता है। निवेशक को किसी भी स्कीम का चुनाव करने के पहले अपनी निवेश अवधि को चुनना चाहिए। एसआईपी के जरिए निवेश से बाजार के सभी टाइमफ्रेम का फायदा निवेशक को मिल जाता है। लंपसम में आप बाजार की गिरावट का फायदा उठा सकते हैं।

नई दिल्ली। आज के समय में निवेश के काफी सारे विकल्प हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड काफी पॉपुलर है। इसमें कोई भी व्यक्ति लंपसम और एसआईपी के जरिए निवेश कर सकता है, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल ये आता है कि दोनों में से सबसे बेहतर विकल्प कौन-सा है। एसआईपी और लंपसम दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं।

SIP के जरिए निवेश फायदे

एसआईपी के जरिए निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बाजार के सभी टाइमफ्रेम का फायदा निवेशक को मिल जाता है। ये एक तरह से ईएमआई की तरह से होता है। हर महीने एक किस्त के रूप में निर्धारित राशि म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर दी जाती है। लंबी अवधि में निवेश के लिए एसआईपी एक अच्छा विकल्प है। इससे लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है।

नुकसान

एसआईपी केवल लंबी अवधि के निवेश के लिए अधिक प्रभावी होता है। म्युचूअल फंड स्कीम में एक निश्चित तारीख को ही एसआईपी जाती है। कई बार देरी होने पर जुर्माना आदि भी भरना पड़ता है। ज्यादातर देखा गया है कि एसआईपी केवल फिक्स इनकम वाले लोगों के लिए अच्छी रहती है।

Lumpsum निवेश फायदे

लंपसम निवेश का एक बड़ा फायदा यह होता है कि आप बाजार की परिस्थिति के मुताबिक निवेश कर सकते हैं। इसमें आप शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए एक बड़ा निवेश करना चाहते हैं और आपकी आय अस्थिर है तो भी लंपसम एक अच्छा तरीका हो सकता है।

उदाहरण के लिए कोरोना के समय जब बाजार में बड़ी गिरावट आई तो म्युचूअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश एक अच्छा मौका था।

नुकसान

लंपसम में निवेश करने का नुकसान यह है कि आप बाजार के सभी टाइमफ्रेम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसका असर आपके रिटर्न पर पड़ता है।

मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी में सबसे अमीर कौन ?

देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं या गौतम अदाणी यह जानने की इच्छा हमेशा रहती है। आज हुरुन की एक लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पछाड़कर देश के सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। जानिए कैसे बने अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति। इस लिस्ट में और कौन-कौन है शामिल। पढ़िए पूरी खबर।

नई दिल्ली: देश में अकसर लोगों के बीच एक सवाल हमेशा रहता है कि आखिर देश का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, मुकेश अंबानी या गौतम अदाणी ?

ये सवाल इस लिए क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को अमीरों की लिस्ट में टक्कर देते हैं। देश के सबसे अमीर लोगों की एक ऐसी ही लिस्ट में आज मुकेश अंबानी ने गौतम अदाणी को पछाड़ दिया। वर्तमान में गौतम अदाणी से आगे निकल कर मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं।

कितनी है अंबानी की संपत्ति ?

360 वन वेल्थ हुरुन इंडिया अमीरों की सूची (360 ONE Wealth Hurun India Rich List 2023) के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज के 66 वर्षीय चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति 2 प्रतिशत बढ़कर 8.08 लाख करोड़ रुपये हो गई, जबकि गौतम अदाणी की संपत्ति 57 प्रतिशत गिरकर 4.74 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

अदाणी पर पड़ा हिंडनबर्ग का असर

हुरुन के प्रबंध निदेशक और मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने अदाणी की संपत्ति में गिरावट के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया।

आपको बता दें कि इस साल के जनवरी में अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अदाणी समूह पर एक रिपोर्ट पेश कर कई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण अदाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी जिसके परिणामस्वरूप गौतम अदाणी के संपत्ति में गिरावट हुई थी। हालांकि गौतम अदाणी ने इन सभी आरोपों से बेबुनियाद बताया था और खारिज किया था।

कुल कितने लोग इस लिस्ट में शामिल ?

हुरुन की इस लिस्ट में 138 शहरों के कुल 1,319 व्यक्तियों का नाम शामिल है। पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला ने तीसरे सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, उनकी संपत्ति 36 प्रतिशत बढ़कर 2.78 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शिव नादर ने चौथे स्थान पर अपना स्थान बरकरार रखा है उनकी संपत्ति 23 फीसदी बढ़कर 2.28 लाख करोड़ रुपये है।

टॉप 10 में कौन-कौन शामिल ?

टॉप 10 की लिस्ट में पांचवे स्थान पर गोपीचंद हिंदुजा, छठे स्थान पर दिलीप सांघवी, सातवें स्थान पर एल एन मित्तल, आठवें स्थान पर राधाकिशन दमानी, नौवें स्थान पर कुमार मंगलम और दसवें स्थान पर नीरज बजाज मौजूद हैं।

'आप' ने अपने कर्मठ और महत्वपूर्ण विभागीय मंत्री ईटीओ को करनाल लोकसभा का प्रभारी बनाया

अमृतसर। (साहिल बेरी) 2024 के लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में जोर-शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं और विभिन्न मंत्रियों और वरिष्ठ आप नेताओं को हरियाणा के अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है. 2016 में, हरभजन सिंह ईटीओ ने उत्पाद शुल्क और कर अधिकारी के पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जिन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान जंडियाला गुरु निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस को हराकर बड़ी जीत हासिल की। ईटीओ ने मान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और बिजली और सार्वजनिक कार्यों के चुनौतीपूर्ण विभागों को संभाला। हाल ही में हुए जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने मंत्री ईटीओ की ड्यूटी भी करतारपुर हलके में लगाई और उनकी कड़ी मेहनत के चलते सुशील कुमार रिंकू करतारपुर हलके से सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा में भेजे गए। आम आदमी पार्टी ने इस कर्मठ और मेहनती मंत्री को हरियाणा लोकसभा वकारी करनाल का प्रभारी नियुक्त कर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का निर्वाचन क्षेत्र है जो काफी चुनौतीपूर्ण होगा. इसके बाद जब हरभजन सिंह ने ईटीओ से बात की तो उन्होंने कहा कि वह आम आदमी पार्टी के एक विनम्र सिपाही हैं, पार्टी जहां भी उनकी ड्यूटी लगाएगी वह पूरी लगन और मेहनत से अपनी ड्यूटी निभाएंगे और हम पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविन्द केजरीवाल जी। हम जी के नेतृत्व में हरियाणा में बड़ी जीत हासिल कर सरकार बनाएंगे।

किसान सम्मान निधि 8000 रुपये करने की तैयारी

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक ,किसान निधि की राशी को 6000 रूपये से बढाकर 8000 रूपये करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में एक प्रस्ताव इसी महीने केंद्रीय केबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इसके लिए बढने वाले खर्च और उससे जुडे अन्य आर्थिक पहलुओं का आंकलन किया जा रहा है।

इस बीच पांच राज्यों के चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इसका भी तोड निकाल लिया है। केन्द्र सरकार केबिनेट में प्रस्ताव पास कराकर चुनाव खत्म होने के बाद फैंसले की घोषणा कर सकती है। क्योंकि इस योजना का फायदा देश के सभी राज्यों के किसानों को होना है। दरअसल केन्द्र की समीक्षा में असल लाभार्थी 11 करोड की जगह 8.51 करोड पाए गए है। यानि ढाई करोड लाभार्थी फर्जी पाए गए है। अब सरकार का मानना है कि फर्जी लाभार्थी रकम करीब 2000 करोड रूपये बढाने से केन्द्र सरकार की ओर से जारी होने वाली कुल रकम नहीं बढेगी।

उल्लेखनीय है कि किसान सम्मान निधि 24 फरवरी-2019 को लागू की गई थी। इसके तहत किसानों को 3 किस्तों में 6000 रूपये सालाना मिलते है। 2019-20 में 9 करोड , 2020-21 में 10 करोड ,2021-22 में 11 करोड किसानों को 6 हजार रूपये सालाना ट्रांसफर किए गए। इसके बाद केन्द्र सरकार ने समीक्षा की तो पात्र लाभार्थियों की संख्या 10.60 करोड रह गई। उसके बाद गहन छानबीन के बाद कुल 8.51 करोड ही रह गई। फर्जी लाभार्थियों के हटने से केन्द्र के किसान सम्मान निधि में 2000 करोड बढ गए है। अब सरकार इसी बढी रकम को प्रति किसान 2000 रूपये और बढाने पर मोहर लगा सकती है।

दो नग्न महिलाओं का बचाव: पीड़िता ने सुनाई मां-बेटी से छेड़छाड़ की दर्दनाक कहानी

मनोरंजन सासमल , ओड़िशा

भुबनेस्वर: सुंदरगढ़ जिले राजरास्ता पर दो नग्न महिलाओं के घूमने की घटना। रेस्क्यू के बाद पीड़िता ने अपनी खौफनाक कहानी सुनाई. मालूम हो कि दोनों रिश्ते में मां-बेटी हैं. झारखंड में अपने गांव में बार-बार शारीरिक शोषण का शिकार होने के बाद वह ओडिशा चले गए। मां-बेटी अभी भी मानसिक तनाव में हैं।

सुंदरगढ़ जिले के सरकारी कॉलेज के सामने 2 महिलाओं के नग्न घूमने की घटना. रेस्क्यू के बाद महिला ने अपनी दुखभरी कहानी बताई. महिला के मुताबिक, जब वे रिश्ते में मां-बेटी थे तब वे झारखंड के रहने वाले थे। उनकी 3 बेटियां हैं. लेकिन, उसी गांव के एक युवक ने अपनी तीन बेटियों पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि विरोध के बाद भी वह तरह-तरह की धमकियां देकर उनकी तीन बेटियों का शारीरिक शोषण कर रहा था। अंत में जब न्याय नहीं मिला तो कोई रास्ता न मिलने पर उन्होंने झारखंड और ओड़िशा छोड़ दिया. हालांकि, शुक्रवार को रेस्क्यू के बाद दोनों महिलाओं को

सुंदरगढ़ के आस्था हाउस में रखा गया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है. एक की उम्र करीब 27 साल और दूसरे की करीब 45 साल बताई जा रही है। दूसरी ओर, एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने आस्था के घर जाकर दोनों पीड़ितों के बयान दर्ज किए और जांच जारी रखी। उनके स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जाती है. उधर, घटना की जांच के लिए सुंदरगढ़ एसपी के नेतृत्व में एक टीम झारखंड गयी है. दो महिलाएं सीमावर्ती झारखंड क्षेत्र की हैं और किसी के शारीरिक शोषण की शिकार महिला की तलाश की जा रही है. सुंदरगढ़ एसपी ने कहा कि महिला को न्याय दिलाया जाएगा.

वहीं दूसरी ओर 2 महिलाओं के सड़क पर नग्न घूमने की खबर से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है. सुंदरगढ़ की कार्यकर्ता कुसुम टेटे की पत्नी ने उन्हें ऐसी हालत में देखा और उनकी मदद की. इससे पहले 2 महिलाओं के नग्न होकर घूमने की दुखद घटना तो सभी ने देखी, लेकिन उनकी मदद करने की बजाय कोई उनकी तस्वीरें लेता नजर आया. मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। हालांकि, सवाल यह उठता है कि शहर के बीचों-बीच साफ रोशनी में और सबके सामने दो महिलाओं को इस हालत में घूमते हुए देखकर किसी को कोई परेशानी नहीं हुई।

भाजपा प्रत्याशी पितलिया एवं भड़ाना का भाजपा कार्यालय पर स्वागत अभिनंदन किया

अनूप कुमार शर्मा, भीलवाडा। भाजपा प्रत्याशी सहाड़ा विधानसभा से लादू लाल पितलिया, मांडल विधानसभा से उदयलाल भड़ाना ने भाजपा जिला कार्यालय पर पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा का स्वागत अभिनंदन किया

भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि भाजपा विधानसभा प्रत्याशी सभी भाजपा जनप्रतिनिधि पदाधिकारी वरिष्ठ कार्यकर्ता कार्यकर्ता सहित सभी समाज संगठन सभी वर्गो को साथ में लेकर भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताना है

भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने भाजपा प्रत्याशी सहाड़ा विधानसभा से लादू लाल पितलिया मांडल विधानसभा से उदयलाल भड़ाना को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर माला साफा पहनाकर भाजपा कार्यालय मे स्वागत अभिनंदन किया इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल गोपाल तेली एस टी मोर्चा जिलाध्यक्ष महेंद्र मीणा पूर्व जिला महामंत्री बाबू लाल टांक उमा शंकर पारीक आईटी जिला संयोजक अजय नौलखा अजीत सिंह केसावत मंडल अध्यक्ष भैरूलाल गाडरी हरी जाट अंकुर बोरदिया चंद्र प्रकाश सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे।

अमृतसर ने कल शाम तक किसानों को धान का 57.18 करोड़ का भुगतान किया - डिप्टी कमिश्नर धान और बासमती की 305289 मीट्रिक टन आवक जंडियाला और टांगरा मंडियों का दौरा किया गया

अमृतसर (साहिल बेरी) - जिले की मंडियों में धान की आवक तेज हो गई है और आखिरी तक शाम 305289 मीट्रिक टन धान और बासमती की आवक हुई है, जिसमें से 53127 मीट्रिक टन धान और 252162 मीट्रिक टन बासमती की आवक हुई है। ये शब्द डिप्टी कमिश्नर श्री अमित तलवार ने गत शाम जंडियाला और टांगरा बाजारों का दौरा करने के बाद व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि अब तक किसानों को 57.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और 24 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान करना सुनिश्चित किया गया है. उन्होंने कहा कि मंडियों में उठान का कार्य भी तेजी से चल रहा है और अब तक 100 प्रतिशत उठान हो चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक सरकारी व निजी एजेंसियों द्वारा 51855 मीट्रिक टन धान तथा 252162 मीट्रिक टन बासमती की खरीद की जा चुकी है। श्री तलवार ने जंडियाला और टांगरा मंडी में किए गए प्रबंधों पर संतुष्टि व्यक्त की। डी.टी. कमिश्नर ने कहा कि जिले में बारदाना, लिफ्टिंग, लेबर संबंधी सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और प्रत्येक उपमंडल में एस.डी.एम. चूंकि नोडल अधिकारी खरीद व्यवस्था देख रहे हैं और उन्हें मंडियों में पहुंचकर खरीद व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धान को सुखाकर ही मंडियों में लाएं ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अमनजीत सिंह, जिला मंडी अधिकारी श्री अमनदीप सिंह के अलावा विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। कैप्शन: डिप्टी कमिश्नर अमृतसर श्री अमित तलवार जंडियाला और टांगरा मंडी का दौरा करते हुए।

लियो क्लब ने करवाया फ्रेन्डली क्रिकेट टूर्नामेंट

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा, भीलवाड़ा। लियो प्रेसिडेंट तोशुभ वागरानी के अनुसार क्लब भीलवाड़ा महाराणा प्रताप व लियो क्लब रॉयल विजयनगर की टीम के बीच फ्रेन्डली क्रिकेट टूर्नामेंट भीलवाड़ा में टर्फ़ पर खेला दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया और इस अवसर पर विजयनगर से आये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लियो नविन चोपड़ा सहित पूरी टीम का भीलवाड़ा क्लब मेम्बर्स द्वारा स्वागत किया गया। मीटिंग में इस माह युवा शक्ति को सेवा कार्य के लिए प्रेरित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के तहत डस्टबीन व नैपकिन वितरित करने का निर्णय लिया गया ।

कमिश्नरेट पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से अमृतसर के इलाकों में ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है. डीसीपी परमिंदर सिंह भंडाल

अमृतसर (साहिल बेरी) इस ट्रैफिक का मुख्य कारण यह है कि संबंधित विभाग शहर के कुछ हिस्सों में राम बाग, बस स्टैंड और वॉल्ड सिटी के आसपास सड़कों की खुदाई कर रहा है। इस संबंध में कमिश्नरेट पुलिस, अमृतसर की ट्रैफिक विंग संबंधित विभागों से बात कर रही है और जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा. 2 कुछ संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए शहर के चौराहों और भंडारी पुल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण शहर में जाम लग जाता है और जनता को यातायात संबंधी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. यदि संगठनों को धरना या विरोध प्रदर्शन करना है तो वह निर्धारित स्थान पर किया जाना चाहिए। 3. आगामी त्यौहार के कारण शहर में सामान्य से अधिक भीड़ है। इसे ध्यान में रखते हुए दुकानदारों से अनुरोध है कि वे अपनी दुकान का सामान बाहर सड़क पर न रखें बल्कि दुकान परिसर के अंदर ही रखें तथा अपने वाहन पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करें तथा ग्राहकों के वाहनों को भी उचित प्रकार से पार्क करें। व्यवस्थाएं, सुरक्षा गार्ड लगाए जाएं और यातायात पुलिस का सहयोग किया जाए। 4. कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर हर दिन सुबह 09:00 बजे एफएम रेडियो के माध्यम से पूरे दिन यातायात के संबंध में एक विशेष बुलेटिन आयोजित करती है, ताकि लोगों को यातायात संबंधी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए बुलेटिन में दी गई यातायात जानकारी अपने अनुसार होती है। .रूट बनाया जाए।

23वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का हुवा शुभारंभ

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। फेडरेशन के प्रवक्ता नारायण भदाला ने बताया की स्व सत्य नारायण भदादा की स्मृति में आयोजित 23वी राज्यस्तरीय टेनिस बोल क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ में अतिथि न्यायाधीश मुकेश भार्गव, पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाडा, पूर्व सभापति ओम नारायणी वाल, उद्योग पति लादू लाल बांगड़, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी, हेमेंद्र शर्मा, बालू राम समदानी, सत्य नारायण पांडया, चैनसुख समदानी, टेनिस बोल रा. अध्यक्ष मुंशी खान, इंटरनेशनल खिलाड़ी कुलदीप राव के आतिथ्य में हुवा ।शकुंतला देवी भदादा व अतिथियों ने सत्यनारायण जी भदादा की तस्वीर के दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण करके प्रतियोगिता को शुरू किया ।टेनिस बोल फेडरेशन के अध्यक्ष महेश पुरी गोस्वामी ने खिलाड़ियों को खेल के द्वारा सरकारी नौकरियों में अपना भाग्य आजमाने पर जोर दिया।

फैडरेशन के सचिव इस्माइल रंगरेज ने बताया की पहले दिन पहले दिन बालक वर्ग में बारा जिले ने टोंक को 5 विकेट से हराया, उदयपुर ने डूंगरपुर को 8 विकेट से, पाली ने राजसमंद को 8 विकेट से और बालिका वर्ग में दौसा ने बीकानेर को 40 रन से हराया। इस दौरान कैलाश भदादा, सतीश भदादा, मनीष भदादा, दीपक भदादा, जय प्रकाश, हर्ष, गर्व, अक्षत, सचिन काबरा, करण पुरी, पुनीत, नरेंद्र आंचलिया, दीपक सोनी, गिरधारी, कपिल सहित टीम सुभाष क्लब के सभी सदस्य गण मौजूद रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023